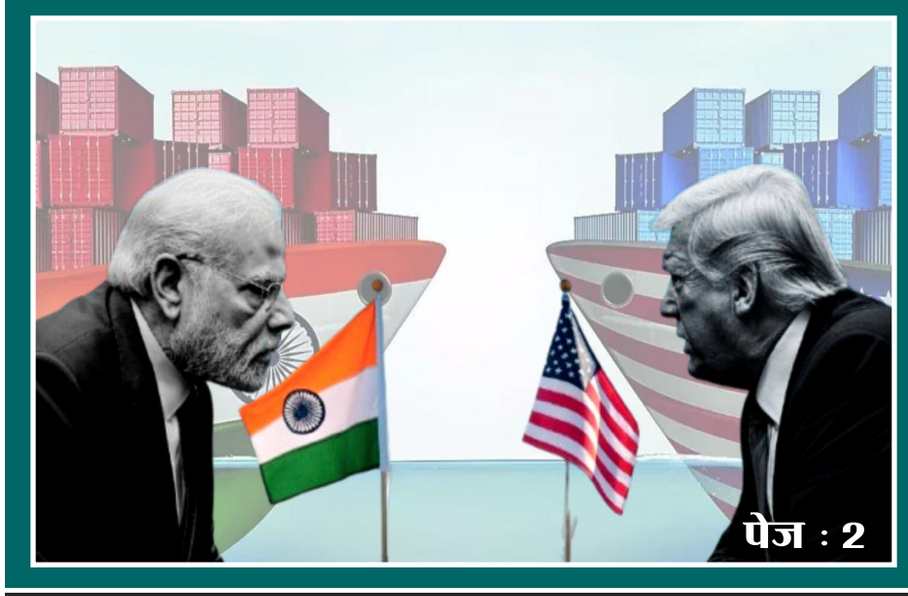

पेज : 2

राष्ट्रीय हिंदी दैनिक

सबसे बड़ी खबर

भव्य खबर

RNI No.- DELHIN/2016/68043

नई दिल्ली संस्करण, नई दिल्ली, शुक्रवार, 04 अप्रैल 2025, वर्ष : 9, अंक : 08 पृष्ठ : 08, मूल्य : 02 रुपया

नई दिल्ली से प्रकाशित व दिल्ली, एनसीआर, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखण्ड, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रसारित

संक्षिप्त समाचार

वर्ष 26-27 में 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली । भारतीय अर्थव्यवस्था वि वर्ष 26 में 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। इसकी वजह चक्रीय रिकवरी और कंर्ट का मजबूत प्रदर्शन करना है। यह जानकारी गुरुवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई। चक्रीय रिकवरी का मतलब उस चरण से है, जहां अर्थव्यवस्था धीमेपन से उभरती है और इस दौरान आर्थिक गतिविधि, कंज्यूमर खर्च और बिजनेस निवेश में बढ़त देखी जाती है। लाइट हाउस कैंटन की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में भारत में मजबूत आय वृद्धि देखी गई है और इस दौरान नि टी इंडे स ने 20 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, विकास का अगला चरण सरकारी पूंजीगत व्यय, मध्यम वर्ग को टै स में दी गई छूट और बेहतर उपभोक्ता मांग जैसे प्रमुख कारकों पर निर्भर करेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि इन कारकों से 2025 में आय में सुधार और बाजार को समर्थन मिलने की उमीद है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के निवेश-आधारित विस्तार ने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पीएम मोदी की वजह से ही हमें सौभाग्यशाली दिन देखने को मिला : कंगना रनौत

नई दिल्ली । सांसद कंगना रनौत ने आज संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा कि व फ संशोधन विधेकक के जरिए भ्रष्टाचार को खत्म किया जा रहा, जो हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है। पीएम मोदी की वजह से ही हमें सौभाग्यशाली दिन देखने को मिला है इस बिल के जरिए सीधा संदेश यही दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या धार्मिक संगठन कानून से ऊपर नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद रनौत ने प्रस्तावित कानून की सराहना की और कहा कि बिल का उद्देश्य भारत में व फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है।

40 हजार कश्मीरी पंडितों को उनकी जमीन वापस नहीं मिली, सरकार को उनकी चिंता करनी चाहिएः संजय राउत

नई दिल्ली । उद्धव ठाकरे की शिवसेना के राज्यसभा संसद संजय राउत ने कहा कि व फ बिल ध्यान भटकाने की कोशिश है। कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन इस मुद्दे को गौण कर दिया गया। और सारा मुद्दा हिंदू मुसलमान पर हो गया। संजय राउत ने आगे कहा कि जब भी बेरोजगारी, मंहगाई का मुद्दा आता है तो धार्मिक मुद्दा उठता है और 2-3-5 दिन आप चर्चा कर लेते हो। साा पक्ष पर सवाल उठाते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि आपको मुस्लिमों की चिंता कब से होनी लगी। आप लोग मुसलमानों को चोर बोलते हो, बोलते हो कि मुस्लिम आपकी जमीन छीन लेंगे, गले की चेन छीन लेंगे। गाय-बैल खोल लेंगे। मुसलमान देशद्रोही हैं, टेरेरिस्ट है। आप लोग मुसलमानों की संपत्ति के रखवाले बने हो। संजय राउत की भाषण के दौरान नारेबाजी होने पर उन्होंने कहा मुझे मत सिखाइए। मैं बहुत पढ़-लिखकर आया हूं यहां। मैंने हिन्दुत्व भी खूब पढ़ा है। संजय राउत ने आगे कहा कि 2025 के पहले की मस्जिद-मदरसों को हाथ नहीं लगाने की बात कही जा रही है। लेकिन आप (केंद्र सरकार) जमीन खरीदने-बेचने की बात पर आ गए हैं। ये आप करके ही रखेंगे। अयोध्या में 13 हजार एकड़ जमीन का घोटाला हुआ। केदारनाथ में 300 किलो सोना गायब हो गया। आप अपनी जमीनों की रक्षा नहीं कर पा रहे, मुस्लिमों की जमीन की रक्षा की बात करते हो। संजय राउत ने आगे कहा कि डिफेंस की जमीनों की रक्षा आप नहीं कर पा रहे हो। आपको अगर जमीन की चिंता है तो कश्मीर के हमारे पंडित भाई हैं, 40 हजार कश्मीरी पंडितों को उनकी जमीन वापस नहीं मिली।

हम लिप सर्विस नहीं, रियल सर्विस करते हैं,राज्यसभा में जेपी नड्डा ने गिनाई वक्फ बिल की खूबियां

नई दिल्ली/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव। राज्यसभा के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि यह देश के हित में है। उन्होंने कहा कि विपक्ष वक्फ विधेयक को बुलडोज करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हूँ और मुझे उम्मीद है कि सदन भी इसका समर्थन करेगा। मुझे उम्मीद है कि उम्मीद (एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तीकरण, दक्षता और विकास) का समर्थन होगा। इस विधेयक का मूल उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में सुधार और उचित प्रबंधन लाना है। इस पर बहुत चर्चा हुई है। नड्डा ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लाए गए इस वक्फ विधेयक को ध्वस्त करने के लिए शोर मचाया जा रहा है। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, मैं इस शोर को रोकता हूँ और इस नैरेटिव का विरोध करता हूँ। उन्होंने कहा कि न्यायालयों में कहा जाता है कि ह्यजब आपके पास तर्क होते हैं, तो आप तर्कपूर्ण होते हैं और उसी के अनुसार बोलते हैं, और जब आपके पास तर्क नहीं होते, तो आप अपनी आवाज उठाते हैं और सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा कि बहस पटरी से उतर गई और भटक गई। मैंने कल लोकसभा में भी यही देखा। जेपी नड्डा ने दावा किया कि वक्फ संशोधन बिल देश के हित में है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल से जवाबदेही बनाने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया। उन्होंने दावा किया कि मुख्यधारा में मुस्लिम बहनों को लाने से कांग्रेस ने रोका है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी कोशिश सिर्फ नियमों के दायरे में लाना है। 2013 में जब वक्फ बिल के लिए जेपीसी का गठन किया गया था, तब इसमें केवल 13 सदस्य थे। लेकिन मोदी सरकार के तहत गठित जेपीसी में 31 सदस्य हैं। जेपीसी ने 36 बैठकें कीं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसकी गतिविधियों पर 200 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया गया। उन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से हमने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय का,

वक्फ की प्रॉपर्टी का सही से उपयोग हो सके। इस बिल में उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रॉपर्टी सही हाथों में रहे।

'भाजपा सरकार के हटने पर नया संशोधन लाएंगे', वक्फ बिल को लेकर बोलीं सीएम ममता बनर्जी

नई दिल्ली/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव। केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया वक्फ संशोधन विधेयक गुरुवार को लोकसभा से पास हो गया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम नया संशोधन लाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा- जब मौजूदा सरकार को हटाकर नई सरकार बनेगी तो हम भाजपा द्वारा लाए गए इस वक्फ विधेयक को निष्प्रभावी करने के लिए एक नया संशोधन लाएंगे। भाजपा देश को बांटने के लिए यह वक्फ विधेयक लाई है। इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को भी एक बयान में भाजपा पर विभाजनकारी एजेंडा लागू करने का आरोप लगाया था और पार्टी की आलोचना की थी। देश को बांटना। वे फूट डालो और राज करो में विश्वास करते हैं। सत्ताधारी एनडीए के नेताओं ने वक्फ संशोधन विधेयक का पुरजोर बचाव किया और इसे अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी बताया है। वहीं, विपक्षी दलों ने इस बिल की निंदा की है और वक्फ संशोधन विधेयक को मुस्लिम विरोधी करार दिया है।

देश की नारी शक्ति पर अब आरएसएस की है नजर

नई दिल्ली/ भव्य खबर/ एजेंसी। भारत के इतिहास में वीरांगनाओं की कहानियां हमेशा प्रेरणादायक रही हैं। चाहे वह 16वीं सदी की रानी अब का हों, जिन्होंने पुर्तगालियों से लोहा लिया या फिर रानी दुर्गावती जिन्होंने मुगलों के खिलाफ वीरतापूर्वक संघर्ष किया। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन ऐतिहासिक नायिकाओं को अपने सांस्कृतिक एजेंडे में खास जगह दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों से आरएसएस इन वीरांगनाओं की जयंती को बड़े स्तर पर मना रहा है। संघ के वरिष्ठ नेता दात्रेय होसबले ने हाल ही में रानी अब का की 500वीं जयंती पर उन्हें एक कुशल प्रशासक और महान रणनीतिकार बताया। इसी तरह, लोकसभा चुनावों से पहले रानी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती भी मनाई गई थी। इन आयोजनों के पीछे संघ की रणनीति पर अब सियासी विश्लेषण शुरू हो गया है। कई सियायी पंडितों का मानना है कि संघ का यह कदम महिलाओं को हिंदुत्व से जोडड़े और महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश है।

यूपी में वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगी 57792 सरकारी संपत्तियां

उत्तर प्रदेश में 98 फीसदी वक्फ संपत्तियों पर खतरा

वक्फ संशोधन बिल लागू होते ही हो जाएगा खेला!

लखनऊ/ भव्य खवर/ रमण श्रीवास्तव। लोकसभा में बुधवार को केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन बिल पेश किया जो विपक्ष के नेताओं हंगामों के बीच पास भी हो गया. अब वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में भी गुरुवार को भी पेश हो गया है और इस पर चर्चा जारी है. इसी बीच वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद यूपी की 98 फीसदी वक्फ संपत्तियों पर खतरा आन पड़ा है. वक्फ संपत्तियों को लेकर एक हिंदी अखबार के अनुसार यूपी की ये वक्फ संपत्तियां अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं, इसलिए इन संपत्तियों के मामलों में अब वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि संबंधित जिलाधिकारी ही फैसला लेने के लिए अधिकृत होंगे. इसके साथ ही यूपी में वक्फ बोर्ड जिन 57792 सरकारी संपत्तियों पर

अपना दावा कर रहा है वह भी उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगी. रिपोर्ट के अनुसार यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एक गोपनीय रिपोर्ट की मानें तो वक्फ बोर्डों ने सार्वजनिक उपयोग की जमीनें भी वक्फ की संपत्ति के रूप में दर्ज कर ली हैं. इतना ही नहीं यूपी के रामपुर और हरदोई जिले समेत कई जिलों में प्राइवेट जमीन को भी गलत तरीके से वक्फ की संपत्ति के रूप में दर्ज करने के कई मामले सामने आए हैं. अब इन सभी मामलों की सुनवाई जिलाधिकारी करेंगे.इस रिपोर्ट की मानें तो उत्तर प्रदेश में 57792 सरकारी संपत्तियां अवैध रूप से वक्फ के नाम पर दर्ज हैं. जिसका रकबा करीब 11712 एकड़ बताया जा रहा है. अब देश में वक्फ संशोधन बिल लागू होते ही ये सभी संपत्तियां वक्फ से बाहर हो जाएंगी. अगर अलीगढ़ मंडल की वक्फ प्रोपर्टी की बात करें तो अलीगढ़ में 1400 वक्फ संपत्तियां हैं जिसमें 1358 सुन्नी और 42 शिया वक्फ की हैं. इसके साथ ही हाथरस में सभी 553 संपत्तियां सुन्नी वक्फ की हैं और कासगंज में कुल 575 संपत्तियों में से 568 सुन्नी और 7 शिया वक्फ की हैं.

वक्फ बिल को समर्थन देने पर जेडीयू में बगावत

●2 मुस्लिम नेताओं ने छोड़ी पार्टी, सीएम नीतीश को लिखा पत्र

पटना/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को गुरुवार को लोकसभा से पास कर दिया गया है। इस बिल को समर्थन देने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद कासिम अंसारी नाराज हो गए हैं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिख कर जदयू के प्राथमिक सदस्य एवं अन्य जिम्मेदारियों से त्याग पत्र दे दिया है। इसके साथ ही ल्पसंख्यक प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मोहम्मद कासिम अंसारी ने सीएम नीतीश कुमार को लिखे गए पत्र में लिखा- "निवदेन पूर्वक कहना है कि हम जैसे लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानो का अटुट विश्वास था कि आप विशुद्ध रूप से सेकुलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं। लेकिन अब यह यकीन टुट गया है। वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2024 के तअलुक से जदयू के स्टैण्ड से हम जैसे लाखों करोड़ों समर्पित भारतीय मुसलमानों एवं कार्यकताओं को गहरा अघात लगा है। हम लोग लोकसभा में ललन सिंह ने जिस तेवर और अंदाज से अपना वकतव्य दिया और इस बिल का समर्थन किया उस से काफी मर्माहत हैं। मोहम्मद कासिम अंसारी ने पत्र में लिखा- "वक्फ बिल हम भारतीय मुसलमानों के विरूद्ध है। हम किसी भी सुरत में इसे स्वीकार नही कर सकते। जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जमुई के आढा के रहने वाले शाहनवाज मलिक ने वक्फ बिल पर जेडीयू के समर्थन के विरोध में ये कदम उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा जारी किया है। मलिक ने सीएम नीतीश को

लिखे अपने पत्र में कहा है कि राज्य के मुसलमानों का कुमार पर से भरोसा टूट गया है। मलिक ने लोकसभा में ललन सिंह के बयान और बिल पर जेडीयू के समर्थन पर नाराजगी जताई है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने को तैयार

30 जज अब तक संपत्तियों की जानकारी दे चुके.....

नई दिल्ली/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने का बड़ा फैसला किया है। बताया जा रहा हैं कि सीजेआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सभी जजों को इस तरह के निर्देश दिए हैं। फिलहाल, इसके तकनीकी पहलुओं पर विचार हो रहा है। खास बात है कि यह फैसला तब आया है, जब जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर कैश मिला था। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों ने फैसला किया है कि वे अपनी संपत्ति का यौरा देने को तैयार है। ये पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलध होगी। 1 अप्रैल को ही सभी न्यायाधीशों की बैठक हुई थी। हालांकि, पहले ही सीजेआई खन्ना सहित कई न्यायाधीश संपत्तियों की जानकारी अदालत को दे चुके हैं, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक अब तक नहीं किए गए थे। फिलहाल, ये आंकड़े कब तक सामने आएंगे, यह भी तय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 30 जज अब तक संपत्तियों की जानकारी दे चुके हैं। इसमें सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस बीवी नागरत्न, जस्टिस एम एम सुंद्रेश, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पीएस नरसिहा, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस पंकज मिल, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस केवी विश्वनाथन, जस्टिस उज्जल भुइयां, जस्टिस एसवी भट्टी, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस पीबी वराले, जस्टिस आर महादेवन, जस्टिस मनमोहन शामिल है।

राहुल गांधी का मोदी सरकार पर आरोप, चीन हमारी जमीन पर कजा करके बैठा

केंद्र सरकार को चीन से अपनी जमीन वापस लेनी चाहिए-राहुल

नई दिल्ली/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में एक बार फिर से चीन द्वारा कब्जाई जमीन का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन में मांग की कि भारत चीन से कब्जाई जमीन वापस ले। राहुल गांधी ने गुरुवार को लोकसभा में चीन से लगी भारतीय सीमा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि चीन भारत की जमीन हथिया कर बैठा हुआ है लेकिन भारत के विदेश सचिव चीन के एंबेसडर के साथ केट काट रहे हैं। गांधी ने कहा कि यह तथ्य है कि चीन 4 हजार किलोमीटर हमारी जमीन पर बैठा हुआ है। मैं हैरान हूं कि कुछ दिन पहले भारतीय विदेश सचिव ने चीन के एंबेसडर के साथ केक काटा। राहुल गांधी ने कहा कि सवाल है कि सीमा पर क्या हुआ। चीन ने 4 हजार किलोमीटर ले लिए हैं। 20 जवान शहीद हुए थे। क्या उनकी शहादत पर केक काटकर यह सेलेब्रेशन था। हम नॉर्मलेंसी के खिलाफ नहीं हैं लेकिन मगर माहौल सामान्य होने से पहले हमें हमारी जमीन वापस मिलनी चाहिए। कांग्रेस सांसद ने कहा कि विदेश मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय मामलों को देखता है। लेकिन हमारे सहयोगी देश 26 फीसदी का टैरिफ हम पर लाद रहे हैं और हम देखते रह रहे हैं। हमारा सारा उद्योग बिखर गया है। ऑटो इंडस्ट्री, टेलीकॉम सब बिखरा पड़ा है। राहुल ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी दादी इंदिरा गांदी का एक किस्सा साझा किया। उन्होंने कहा कि किसी ने विदेश मामलों को लेकर एक बार इंदिरा गांधी से पूछा था कि आप राइट या लेफ्ट किधर जाना चाहेंगी? तब इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं न लेफ्ट जाऊंगी न राइट बल्कि मैं सीधी तनकर खड़ी हो जाऊंगी। मैं भारतीय हूं और सीधी खड़ी रहूंगी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से मांग की कि उन्हें बताना चाहिए कि

हमारे सहयोगी देश टैरिफ लाद रहे हैं। चीन ने जमीन कब्जा कर ली है, सरकार इन मसलों पर क्या कर रही है।

●लोकसभा में एक दिन पहले ही 12 घंटे से ज्यादा की मैराथन चर्चा के बाद पारित हुआ था वक्फ बिल

रात 2 बजकर 32 मिनट पर राज्यसभा में भी पास हुआ वक्फ संशोधन बिल

नई दिल्ली/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव। वक्फ संशोधन बिल पर संसद की मुहर लग गई है। राज्यसभा में बिल पर चर्चा पूरी होने के बाद देर रात 2 बजे के बाद वोटिंग कराई गई। इस दौरान सत्ता पक्ष बिल पास कराने में सफल रहा। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। इस तरह 12 घंटे से ज्यादा की चर्चा के बाद रात 2.32 बजे राज्यसभा से वक्फ विधेयक पारित हो गया। सत्ता पक्ष ने बिल को वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकलकर राष्ट्रीय हित की ओर बढ़ाया गया कदम बताया। वहीं विपक्ष ने बिल को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ करार दिया। चर्चा के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष की ओर से कई मौकों पर गहमागहमी की स्थिति भी देखने को मिली। हालांकि, लोकसभा से बिल पास होने के अगले ही दिन राज्यसभा से भी वक्फ बिल पारित हो गया।

'वक्फ बिल से एक मुसलमान का नुकसान नहीं होने वाला'

राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक बिल से किसी एक मुसलमान का नुकसान नहीं होने वाला, करोड़ों गरीब मुसलमानों का फायदा होने वाला है। बिल पास होने के बाद देखिएगा कैसे लोग इसका स्वागत करते हैं। रिजिजू ने इस दौरान विपक्ष पर अटैक करते हुए कि हम नहीं, मुसलमानों को आप डरा रहे हैं। उन्हें मुख्यधारा से बाहर करने की कोशिश कर रहे।

'मुसलमानों में गरीबी है तो ये कांग्रेस का फेल्योर'

रिजिजू ने कांग्रेस पर अटैक करते हुए कहा कि आजादी के बाद 60 साल आपने शासन किया। फिर भी मुसलमानों में गरीबी है तो ये फेल्योर आपका है। आप जो काम नहीं कर पाए, वह पीएम मोदी को करना पड़ रहा है। दिनभर इतने वरिष्ठ लोग अपना ही पदार्फाश कर रहे थे। सोच रहा था कि बाहर बोलूंगा। वक्फ प्रॉपर्टी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। कोई कर भी नहीं सकता। गैर मुस्लिम किसी धार्मिक बॉडी में सदस्य नहीं बनेगा। वक्फ बोर्ड एक स्टैचुएटरी बॉडी होती है।

वक्फ बिल पर राज्यसभा में भी लंबी बहस

राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने इस बिल को राष्ट्रहित में बताया है। यह भी कहा कि बिल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सही मैनेजमेंट करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है, ताकि गरीब मुस्लिमों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। जेपी नड्डा ने कहा, 'विपक्ष मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा है।

किरेन रिजिजू ने पेश किया बिल

राज्यसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार दोपहर एक बजे राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। रिजिजू ने कहा कि 2006 में आई सच्चर कमिटी की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय देश में 4.9 लाख वक्फ संपत्तियां थी, जिनसे होने वाली आय केवल 163 करोड़ रुपये सालाना थी। आज के दिन 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। अगर इनको ठीक से मैनेज किया जाए तो हजारों करोड़ रुपये की इनकम हो सकती है, जिसका फायदा गरीब मुसलमानों को मिल सकता है।

विपक्ष ने बिल को बताया संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ

वहीं विपक्ष ने इस बिल को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस सांसद और

वक्फ पर जेपीसी के सदस्य नसीर हुसैन ने सरकार पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स का आरोप लगाया। उन्होंने जेपीसी में विपक्ष की ना सुनी जाने और एनडीए पक्ष की ओर से दी गई सिफारिशों को देश की जनता पर थोपने का आरोप लगाया।

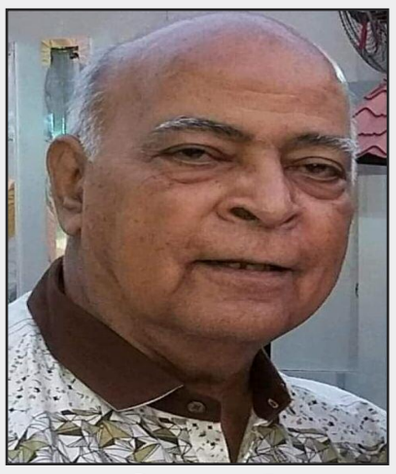

ट्रंप टैरिफ का भारत पर क्या असर पड़ेगा

अशोक भाटिया

डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को वह कर दिया है, जिसकी धमकी वह वॉइट हाउस में वापसी के बाद से दे रहे थे। उन्होंने दुनियाभर के देशों के खिलाफ व्यापक टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी, जिसमें भारत भी शामिल है। ट्रंप ने जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान करते हुए इसे अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस बताया।

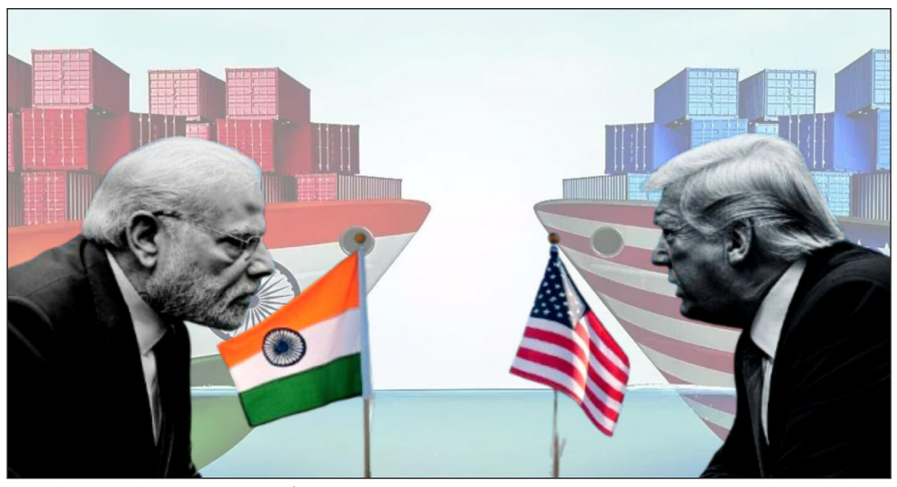

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को वह कर दिया है, जिसकी धमकी वह वॉइट हाउस में वापसी के बाद से दे रहे थे। उन्होंने बुधवार को दुनियाभर के देशों के खिलाफ व्यापक टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी, जिसमें भारत भी शामिल है। ट्रंप ने जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान करते हुए इसे अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस बताया। वॉइट हाउस के रोज गार्डन में बोलते हुए ट्रंप ने कहा, 'यह हमारी स्वतंत्रता की घोषणा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26 फीसदी टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा करते हुए कहा यह मुक्ति दिवस है, एक ऐसा दिन जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 2 अप्रैल 2025 को हमेशा उस दिन के रूप में याद किया जाएगा जिस दिन अमेरिकी इंडस्ट्री का पुनर्जन्म हुआ था, जिस दिन अमेरिका की नियति को फिर से प्राप्त किया गया था, और जिस दिन हमने अमेरिका को फिर से अमीर बनाना शुरू किया था, हम इसे अमीर, अच्छा और अमीर बनाने जा रहे थे। ट्रंप के भारत सहित दुनिया के कई देशों पर लगाए गए टैरिफ ने चौतरफा ट्रेड वॉर की आशंका को बढ़ा दिया है। ट्रंप ने कहा कि हमारे देश को अन्य देशों द्वारा लूटा गया है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि करदाताओं को 50 से अधिक वर्षों से लूटा जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा, "मैं दुनिया भर के देशों पर पारस्परिक (रेसिप्रोकल) टैरिफ लगाने वाले एक ऐतिहासिक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। रेसिप्रोकल, इसका मतलब है कि वे हमारे साथ जैसा कर रहे हैं, वैसा ही हम उनके साथ करेंगे। ट्रंप ने विदेश से आने वाली सभी वस्तुओं पर 10% से लेकर 49% तक टैरिफ लगाने की घोषणा की। इनमें भारत से आने वाले सामानों पर 26% टैरिफ के अलावा चीन से आने वाले सामानों पर 34% टैरिफ, यूरोपीय संघ से आने वाले सामानों पर 20% टैरिफ और यूनाइटेड किंगडम से आने वाले सामानों पर 10% टैरिफ शामिल है। साथ ही वियतनाम पर 46% टैरिफ, ताइवान पर 32%, जापान पर 24%, दक्षिण कोरिया पर 25%, थाईलैंड पर 36% और कंबोडिया पर 49%। अगर रेंज देखें तो तमाम देशों पर 10% से लेकर 49% तक के व्यापक टैरिफ लागू किए हैं। ज्ञात हो कि पिछले कुछ हफ्तों में भारत ने भी अपने टैरिफ सिस्टम में बदलाव किया है। भारत ने 8,500 औद्योगिक वस्तुओं पर आयात शुल्क कम कर दिया है। इनमें अमेरिकी सामान जैसे कि बर्बन व्हिस्की और हार्ले-डेविडसन की महंगी मोटरसाइकिलें शामिल हैं। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति की एक पुरानी शिकायत दूर हो गई है। भारत ने यह भी संकेत दिया है कि वह अमेरिका से ज्यादा तेल, एलएनजी और रक्षा उपकरण खरीदेगा। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि आगे और भी टैरिफ में कटौती की जाएगी। ट्रंप के ताजा टैरिफ से भारत पर अपने टैरिफ सिस्टम में और भी ज्यादा कटौती करने का दबाव बढ़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबक भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शुल्क में कटौती की अमेरिकी मांगों पर विचार कर रहा है। नए टैरिफ से भारत पर गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं को हटाने का भी दबाव बढ़ सकता है। इनमें कुछ आयातों पर अपारदर्शी आयात प्रतिबंध और लाइसेंसिंग आवश्यकताएं शामिल हैं। अपारदर्शी का मतलब है कि ये नियम और प्रतिबंध स्पष्ट नहीं हैं और आसानी से समझ में नहीं आते हैं। मौजूदा तथ्यों के बावजूद कि भारत और अमेरिका को किसी भी आर्थिक मानदंड पर समान नहीं किया जा सकता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की 2 अप्रैल से अमेरिका की यात्रा के दौरान घोषणा की कि भारतीय उत्पादों पर समान आयात शुल्क लगाया जाएगा। वास्तव में, ट्रम्प के दूसरी बार पद संभालने के बाद मोदी की यह पहली अमेरिका यात्रा थी। लेकिन फिर भी, ट्रम्प ने सभी राजनयिक प्रोटोकॉल को एक तरफ रख दिया और भारत पर एक समान आयात शुल्क की घोषणा की। यह भारत की दूसरी उपमा है। इससे पहले, ट्रम्प प्रशासन ने उन्हें हाथों-हाथ सैन्य विमान पर घर भेजकर हमारा अपमान किया था। उस समय, हमने वास्तव में अमेरिकी कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन यह नहीं मिला, क्योंकि जब मोदी अमेरिका में थे, तब भी अमेरिका भारतीय शरणार्थियों पर यही कर भेजता रहा। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में आ जाएगा। दरअसल, भारतीय उद्यमी इस उम्मीद में जी रहे थे कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती उन्हें बचा लेगी। लेकिन ऐसा होने के कोई संकेत नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि अंतिम समय में "ट्रम्पोजी के दिमाग में आओ" कहकर भारत के बैग में कुछ रियायतें नहीं डाली जाएंगी। लेकिन यह संभावना धूमिल लगती है। ऐसी स्थिति में, हमें यह अनुमान लगाने की आवश्यकता है कि यदि यह आयात कर समानता वास्तविकता बन जाती है तो क्या होगा। कृषि उत्पाद, मोटर और संबंधित उद्योग, दवाएं और शराब चार कारक हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के गुस्से का कारण बने हैं। यह अमेरिका की शिकायत है। ट्रम्प ने पहले अल्ट्रा-रिच हार्ले-डेविडसन पर भारत में लगाए गए कर पर टिप्पणी की थी। शुरू में, उन्होंने इसे नजर-अंदाज कर दिया। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि मामला गंभीर है, तो ट्रम्प संतुष्ट नहीं दिखे। वह संतुष्ट नहीं लग रहे हैं। वह चाहते हैं कि भारत मोटर उद्योग से संबंधित सभी करों में कटौती करे। दूसरा मुद्दा दवाओं का है। हम चीन के बाद सबसे बड़े थोक दवा निमार्ता हैं। हम इससे रसायन बनाते हैं। उन्हें अमेरिकी कंपनियों द्वारा खरीदा जाता है। अमरीका उन पर लगाए गए आयात शुल्क को स्वीकार नहीं करता है जब उन्हें अंतिम रूप से भेषज उत्पादों में परिवतत किया जाता है और वे भारतीय बाजार में आते हैं। हम स्थानीय उत्पादों को आकर्षक बनाने के लिए विदेशी आयातित वस्तुओं/उत्पादों पर आयात कर लगाते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि रेट कम किया जाए। शराब बनाने के 'उनके' नियमों के कारण, हम कहते हैं कि हमें उन्हें लागू नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में अधिक गर्मी है, यह तर्क कि शराब कम समय में मर जाती है, अमेरिकी देशों को स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हमारी शराब पर प्रतिबंध हैं और हम देखते हैं कि उनकी शराब कैसे अधिक से अधिक महंगी हो जाएगी। ट्रम्प इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए, उनकी स्थिति यह है कि भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में उतना ही कर लगाया जाना चाहिए जितना भारत इन चार घटकों में अमेरिकी उत्पादों पर लगाता है। इसका मतलब है कि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद और महंगे हो जाएंगे और उनकी मांग घट जाएगी। दूसरे शब्दों में, इन उत्पादों के भारतीय निमार्ता प्रभावित होंगे। नतीजतन, हमारी पहले से ही धीमी अर्थव्यवस्था और भी धीमी हो जाएगी। इससे बचने के लिए हमारे सामने एक ही उपाय है कि हम अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क कम करें। ट्रंप की बयानबाजी यह है कि उन्होंने पारस्परिक रूप से यह भी कहा है कि भारत आयात करों की मात्रा कम करने के लिए तैयार है। ये कटौती वास्तव में हो रही है या नहीं, यह अब पता चलेगा। लेकिन ऐसा करना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिकी बयान ने भारत सरकार के एक और मुद्दे पर अपनी नाराजगी व्यक्त की: सरकार के नियम बदल जाते हैं, उदाहरण के लिए, एप्पल, अमेजॅन और फेसबुक जैसी कंपनियों के पास कंप्यूटर होना चाहिए जो भारत में अपने उपयोगकताओं की जानकारी संग्रहीत करते हैं, या मास्टरकार्ड और वीजा जैसे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले भारतीय उपभोक्ताओं पर इसी तरह का आदेश। लैपटॉप आयात पर प्रतिबंध जैसे मुद्दे हैं। यह कहना मुश्किल है कि वे उचित नहीं हैं। खेल शुरू करने के बीच में नियमों को बदलने की यह प्रवृत्ति वास्तव में भारतीय उद्यमियों के लिए भी एक समस्या है। लेकिन क्योंकि उनके पास इसके बारे में शिकायत करने का साहस नहीं है, ये भारतीय उद्यमी झुकते हैं और सभी 'दिनचर्या' को सहन करते हैं। देश तो यहां तक आ गया है कि इस सरकारी प्रथा से अपनी नाराजगी सार्वजनिक रूप से जाहिर कर रहा है और आपके पास इस मुद्दे पर भी पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नतीजतन, ऐसे संकेत हैं कि लैपटॉप आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय उलट दिया जाएगा। जिन मुद्दों पर वापसी होगी, उनके विवरण की घोषणा अब की जाएगी।अमेरिका में ट्रम्प की गवाही ने उनके नारे 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' उर्फ 'मागा' को 'मेक इंडिया ग्रेट अगेन' उर्फ 'मिगा' के रूप में संदर्भित किया। यह अच्छा है, लेकिन असली चुनौती 'मागा' के सामने 'मिगा' को बनाए रखना है। यह सवाल पूछना अधिक विचारोत्तेजक है।

संपादकीय

बुलडोजर पर प्रहार

अमृता आर. पंडित

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुलडोजर से घर ढहाने को सुप्रीम कोर्ट ने अमानवीय और अवैध करार देते हुए कहा कि इससे अदालत की आत्मा को झटका लगा है। उप्र सरकार को प्रत्येक परिवार को दस लाख रुपये का मुआवजा देने के साथ अधिकारियों को उनकी अत्याचारिता के लिए सबक सिखाने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि इस देश में आश्रय का अधिकार, कानून की उचित प्रक्रिया और कानून का शासन जैसी कोई चीज है। आवासीय परिसरों को मनमाने तरीके से ध्वस्त करने पर विकास अधिकारियों को यह याद रखने को कहा कि आश्रय का अधिकार मौलिक अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 21(जीवन व स्वतंत्रता) का अभिन्न अंग है। सभी छह याचिकाकर्ता इलाहाबाद के लूकरगंज के निवासी हैं जिनके घर मार्च, 2021 में बुलडोजर से ध्वस्त किए गए थे। उनका कहना है कि स्थानीय अधिकारियों ने गलत धारणाओं के आधार पर घर गिराया कि वे माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की संपत्तियां हैं। शीर्ष अदालत ने अंबेडकरनगर जिले में बुलडोजर कार्रवाई का भी हवाला दिया। झोपड़ियों को ध्वस्त किए जाने पर कहा कि वह बहुत परेशान करने वाला और चौंकाने वाला है। उप्र सरकार के वकील ने दलील दी कि ये मकान अवैध थे इसलिए ध्वस्त किए गए। इनके साथ अन्य संपत्तियां भी ढहाई गई। हैरत है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तोड़-फोड़ की इस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। राज्य सरकार का दावा था कि बुलडोजर कार्रवाई पेशेवर अपराधियों और माफिया के खिलाफ की गई। इस हकीकत के बावजूद सरकारी तंत्र को उचित नोटिस देने के साथ ही रहवासियों को कागजात दिखाने और मालिकाना साबित करने का वक्त देना चाहिए था।

चिंतन-मनन

द्वंद्व के बीच शांति की खोज

केवल ज्ञान की बातें करों। किसी व्यक्ति के बारे में दूसरे व्यक्ति से सुनी बातें मत दोहराओ। जब कोई व्यक्ति तुम्हें नकारात्मक बातें कहे, तो उसे वहीं रोक दो, उस पर वास भी मत करो। यदि कोई तुम पर कुछ आरोप लगाये, तो उस पर वास न करो। यह जान लो कि वह बस तुम्हारे बुरे कर्मो को ले रहा है और उसे छोड़ दो। यदि तुम गुरु के निकटतम में से एक हो तो संसार के सारे आरोपों को हंसते हुए ले लोगे।

द्वद्व संसार का स्वभाव है और शांति आत्मा का स्वभाव है।

द्वद्व के बीच शान्ति की खोज करो। द्वद्व समाप्त करने की चेष्टा द्वद्व को और ज्यादा बढ़ाती है। आत्मा की शरण में आकर विरोध के साथ रहो। जब शान्ति से मन ऊबने लगे तो सांसारिक क्रिया-कलापों का मजा लो। और जब इनसे थक जाओ तो आत्मा की शान्ति में आ जाओ।

यदि तुम गुरु के करीब हो, तो दोनों क्रिया कलाप साथ-साथ करोगे।

ईश्वर व्यापक हैं। और अन्नत काल से ईश्वर सभी विरोधों को संभालते आए हैं। यदि ईश्वर सारे विरोधों को ले सकते हैं, तो निश्चित ही तुम भी ऐसा कर सकते हो। जैसे ही तुम विरोध के साथ रहना स्वीकार कर लेते हो, विरोध स्वतः समाप्त हो जाता है।

शान्ति चाहने वाले लोग लड़ना नहीं चाहते और इसके विपरीत लड़ाई करने वाले शान्ति पसन्द नहीं करते। शान्ति चाहने वाले लड़ाई से बचना चाहते हैं। आवश्यक यह है कि मन को शांत करें और फिर लड़ें। गीता की यही मूल शिक्षा है। कृष्ण अजरुन को उपदेश देते हैं कि अजरुन युद्ध करो मगर ह्दय को शान्त रखकर।

संसार में जैसे ही तुम एक विरोध को समाप्त करते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ही रूस की समस्या समाप्त हुई, बोस्निया की समस्या खड़ी हो गई। एक समस्या हल होती है, तो दूसरी शुरू हो जाती है। तुम्हें जुकाम हुआ।

वह जरा ठीक हुआ नहीं कि फिर कमर में दर्द शुरू हो गया।

फिर यह ठीक हो गया। और तो और, शरीर ठीक ठाक है तो मन अशान्त हो जाता है। बिना किसी इरादे के गलतफहमियां पैदा होती हैं, उलझन पैदा होती है। यह तुम्हारे ऊपर नहीं कि तुम उनका समाधान करो। तुम तो बस उन पर ध्यान न दो, बस जीवन्त रहो।

संघ-भाजपा में तालमेल से जुड़े सुखद संकेत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 25 साल बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय के अंगने में पहुंचकर संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर (गुरुजी) के स्मारक स्मृति मंदिर में श्रद्धांजलि दी, जिससे संघ एवं भाजपा के बीच एक नई तरह की ऊर्जामयी सोच एवं समझ विकसित हुई है। एक नई प्राणवान ऊर्जा का सूरज उगा है, नये संकल्पों को पंख लगे हैं। संघ के सौ वर्ष पूरे करने के ऐतिहासिक अवसर पर मोदी ने सही कहा कि संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है, जो निरंतर भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 34 मिनट की संबोधन में देश के इतिहास, भक्ति आंदोलन, इसमें संतों की भूमिका, संघ की निःस्वार्थ कार्य प्रणाली, देश के विकास, युवाओं में धर्म-संस्कृति, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा, भाषा और प्रयागराज महाकुंभ की चर्चा करते हुए जहां नये बन रहे भारत की बानगी प्रस्तुत की, वही संघ की उपयोगिता एवं महत्व को चार-चांद लगाये। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की संघ के मुख्यालय की इस पहली यात्रा के गहरे निहितार्थ भी हैं तो दूरगामी परिदृश्य भी है। जो इस बात का संकेत है कि पिछले आम चुनाव के दौरान संघ व भाजपा के रिश्तों में जिस खटास को अनुभव किया गया था, वह संवाद, समझ, सकारात्मक सोच व संपर्क से दूर कर ली गई है। जो इस बात का भी संकेत है कि आने वाले वक्त में भाजपा व सरकार के अहम फैसलों में संघ की भूमिका बढ़ेगी, जिससे देश हिन्दू राष्ट्र के रूप में सशक्त होते हुए विश्व गुरु बनने के अपने संकल्प को पूरा कर सकेगा। वसुधैव कुटुम्बकम के भारत के उद्घोष को अधिक सार्थक करते हुए दुनिया के लिये एक रोशनी बनेगा। यह सर्वविदित है कि मोदी भी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। साथ ही वे संघ की रीति-नीतियों से भली-भांति परिचित हैं। लेकिन पिछले आम चुनाव के दौरान भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं के कुछ अतिश्योक्तिपूर्ण एवं अहंकारी बयानों से भाजपा का कद संघ से बड़ा बताने की कोशिशें हुई थी, जिसके चलते संघ व भाजपा के रिश्तों में कुछ कसक एवं खटास देखी गई। जिसका असर लोकसभा चुनाव में चार सौ पार के लक्ष्य पर पड़ा, उसके मूल में संघ कार्यकताओं की उदासीनता रही है। बाद में दोनों के रिश्ते सामान्य होने के बाद हरियाणा, महाराष्ट,ज छत्तीसगढ़ एवं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जो आशातीत सफलता हाथ लगी, कहा जा रहा था कि उसमें संघ कार्यकताओं का समर्पण व सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण घटक रहा। अब संघ मुख्यालय में प्रधानमंत्री की यात्रा से यह तथ्य भी उजागर हुआ कि दोनों की रीतियों नीतियों फिर से बेहतर तालमेल स्थापित हुआ है। इसका असर आने वाले दिनों में भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में संघ की भूमिका को लेकर देखने को मिलेगा, ऐसा ही असर बदलते वक्त के साथ पार्टी के अन्य फैसलों पर भी नजर आ सकता है। आने वाले समय में भाजपा के लिये संघ का सहयोग पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अपनी जमीन मजबूत करने एवं जड़े जमाने में मील का पत्थर साबित होगा। इन राज्यों में संघ अपनी आधार भूमि को विस्तार दे रहा है। यानी दोनों अब सामंजस्य, सहयोग व सहजता के साथ आगे बढ़ेंगे। अर्थात भाजपा अब अपने वैचारिक एवं ऊर्जा स्त्रोत के साथ बेहतर तालमेल करके चलना चाहेगी। मोदी की नागपुर यात्रा के अनेक शुभ संकेत देखे जा रहे हैं, इसको औरंगजेब, राणा सांगा, संभल विवाद के बीच हिन्दुत्व की राजनीति को नई धार देने की कोई योजना के साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है, नरेन्द्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की इस मुलाकात को 2029 के चुनावों की कोई नई पटकथा तैयार करने की पृष्ठभूमि में भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के संघ मुख्यालय के दौरे पर जहां विपक्ष बौखला रहा है वहीं इस यात्रा ने संघ के भीतर भी कई लोगों को सुखद आश्चर्य में डाल दिया है। मोदी दीक्षाभूमि भी गए, जहां डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर ने 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। उन्होंने दीक्षाभूमि की सामाजिक न्याय और दलितों को सशक्त बनाने के प्रतीक के रूप में सराहना करते हुए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के सपनों के भारत को साकार करने के लिए और भी अधिक मेहनत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहरा कर सबका दिल जीत लिया। मोदी की ओर से नागपुर में अपने संबोधन के दौरान संघ की भरपूर प्रशंसा को अपने वैचारिक मार्गदर्शक के प्रति भाजपा के रुख में आये बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। मोदी ने संघ की ह्यराष्ट्र निर्माण और विकास में रचनात्मक भूमिकाह्ल को रेखांकित करके अपनी ह्य2047 तक विकसित भारतह्ल की योजनाओं में संघ की भूमिका के महत्व को भी दशार्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज में हाल ही में संपन्न महाकुंभ मेले में ह्लमहत्वपूर्ण भूमिकाह्व निभाने के लिए भी स्वयंसेवकों को श्रेय दिया था। इसके अलावा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों पर आर-एसएस द्वारा की जाने वाली सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने पर लगाए गए प्रतिबंध को भी हटा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने जीवन-संकल्पों एवं विचार-ऊर्जा के जिस आंगन में आठ वर्ष की आयु में कदम रख कर जीने की कला सीखी।

"मैं नास्तिक क्यों हूँ"

राजेश श्रीवास्तव

एक ऐतिहासिक और विचारोत्तेजक लेख, "मैं नास्तिक क्यों हूँ," भगत सिंह द्वारा 5-6 अक्टूबर 1930 को लाहौर सेंट्रल जेल में लिखा गया था। यह केवल उनके व्यक्तिगत धार्मिक विश्वासों पर नहीं, बल्कि समाज, तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और क्रांतिकारी विचारधारा पर गहन आत्ममंथन प्रस्तुत करता है।

भगत सिंह स्पष्ट करते हैं कि उनका नास्तिक होना कोई विद्रोही प्रवृत्ति का परिणाम नहीं था, बल्कि यह तर्क, अध्ययन और आत्मविश्लेषण से उपजा विचार था। उन्होंने इसे अपने अहंकार का प्रतीक मानने वाले लोगों को जवाब देने के लिए लिखा था। वे कहते हैं–

"यह कहना कि मैं नास्तिक इसलिए बना क्योंकि मैं अहंकारी हूँ, बिल्कुल गलत है। यह अहंकार नहीं, बल्कि तर्क और विवेक का परिणाम है।"

यह लेख भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी विचारधारा और आधुनिक समाज में तर्कशीलता की आवश्यकता को दशार्ता है।

भगत सिंह अपने प्रारंभिक जीवन में धार्मिक आस्थाओं में विश्वास रखते थे, लेकिन जब उन्होंने समाज, इतिहास और क्रांतिकारी विचारों का अध्ययन किया, तो उनका नजरिया बदलने लगा। वे लिखते हैं–

"जब मैंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया, तब मैं ईश्वर में विश्वास करता था। लेकिन धीरे-धीरे, जैसे-जैसे मैंने चीजों को गहराई से समझना शुरू किया, मुझे एहसास हुआ कि ईश्वर का अस्तित्व केवल एक कल्पना है।"

वे बताते हैं कि जब वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (ल्लरफ्अ) से जुड़े, तब तक वे ईश्वर को मानते थे, लेकिन तर्क, विज्ञान और समाजवादी साहित्य के अध्ययन के बाद उनका यह विश्वास समाप्त हो गया। उन्होंने मार्क्स, लेनिन और अन्य समाजवादी विचारकों का अध्ययन किया, जिसने उनके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया।

भगत सिंह इस लेख में बताते हैं कि धर्म का उपयोग अक्सर सत्ता और समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों द्वारा जनता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

"धर्म शोषकों का एक औजार है, जो गरीब और कमजोर वर्गों को यह विश्वास दिलाता है कि उनकी गरीबी और दुख-दर्द उनकी किस्मत का हिस्सा हैं।"

वे इस विचारधारा का विरोध करते हैं और मानते हैं कि जब तक लोग ईश्वर पर निर्भर रहेंगे, तब तक वे अन्याय के खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे।

भगत सिंह ने तर्क दिया कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान और न्यायप्रिय है, तो समाज में अन्याय और अत्याचार क्यों है?

"यदि ईश्वर गरीबों की रक्षा करने वाला है, तो इतने वर्षों से भारत गुलाम क्यों है? अगर वह न्यायप्रिय है, तो हजारों निर्दोष लोग क्यों मारे जाते हैं?"

वे एपिक्यूरस की दुविधा का उल्लेख करते हैं, जो ईश्वर की सर्वशक्तिमानता और दयालुता पर सवाल उठाती है। वे पूछते हैं कि यदि ईश्वर अन्याय रोक सकता है, लेकिन रोकता नहीं, तो वह दयालु नहीं। यदि वह रोकना चाहता है, लेकिन रोक नहीं सकता, तो वह सर्वशक्तिमान नहीं।

यह तर्क भगत सिंह की वैज्ञानिक और तार्किक सोच को दशार्ता है। वे केवल विश्वास के आधार पर किसी भी विचार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे।

जब भगत सिंह ने नास्तिकता को अपनाया, तो समाज ने उन पर घमंड और अहंकार का आरोप लगाया। उन्होंने इस धारणा को पूरी तरह से खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि नास्तिकता उनके अहंकार का परिणाम नहीं, बल्कि गहन अध्ययन और तर्क का परिणाम थी।

"यदि मैं मृत्यु के डर से ईश्वर को मान लूं, तो यह मेरी नास्तिकता की पराजय होगी।"

वे यह भी कहते हैं कि अक्सर लोग मृत्यु के निकट आकर ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। वे अपनी अंतिम सांस तक अपने विचारों पर अडिग रहने का संकल्प लेते हैं।

भगत सिंह को यह अहसास था कि मृत्यु के निकट आते ही लोग अक्सर ईश्वर की शरण में चले जाते हैं। लेकिन वे दृढ़ता से कहते हैं–

"कुछ लोग कहते हैं कि जब मृत्यु सामने आती है, तो व्यक्ति का अहंकार चूर-चूर हो जाता है। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा नास्तिक रहना मेरी समझदारी और विचारशीलता की परीक्षा है।"

वे मानते थे कि ईश्वर में आस्था केवल एक भय का परिणाम है। लेकिन वे किसी भी भय के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं थे।

आज के दौर में, जब धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास फिर से समाज में गहराई से अपनी जड़ें जमा रहे हैं, भगत सिंह का यह लेख एक प्रेरणा बन सकता है।

यह हमें सिखाता है कि किसी भी विचार या विश्वास को केवल परंपरा के आधार पर नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि उसे तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखना चाहिए।

"हमारा समाज तभी आगे बढ़ेगा, जब हम तर्क, विज्ञान और स्वतंत्र सोच को अपनाएंगे।"

युवाओं के लिए यह लेख एक संदेश है कि वे अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से विकसित करें और बिना भय के तर्कपूर्ण सोच को अपनाएं।

यह लेख एक संदेश है–अंधविश्वास से मुक्त होकर तर्कसंगत सोच अपनाने का। यही सच्ची क्रांति की पहली शर्त है!

"मैं नास्तिक क्यों हूँ" केवल एक व्यक्तिगत विचार नहीं, बल्कि एक बौद्धिक क्रांति का दस्तावेज है।

भगत सिंह ने यह स्पष्ट किया कि सच्चा क्रांतिकारी वही हो सकता है, जो तर्क, विज्ञान और आत्मविश्लेषण पर विश्वास करता हो। उनका यह लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी मान्यताओं को तर्क की कसौटी पर परखने के लिए तैयार हैं?

आज, जब समाज में कट्टरता और अंधविश्वास पुनः गहराते जा रहे हैं, हमें भगत सिंह की विचारधारा को समझने और आत्मसात करने की आवश्यकता है। उन्होंने हमें सिखाया कि डर के कारण या परंपराओं के बोझ तले दबकर किसी भी विचार को स्वीकार करना हमारी सोच को सीमित कर देता है। उनकी यह नास्तिकता केवल ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न नहीं उठाती, बल्कि यह सोचने की उस स्वतंत्रता की ओर भी संकेत करती है, जो किसी भी व्यक्ति को सच्चे अर्थों में मुक्त बनाती है।

यदि हम वास्तव में समाज को न्यायसंगत, वैज्ञानिक और प्रगतिशील बनाना चाहते हैं, तो हमें हर विश्वास को तर्क और विवेक की कसौटी पर परखना होगा। भगत सिंह की विचारधारा केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक भी है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस मार्ग पर चलने का साहस रखते हैं या नहीं।

अदालत ने आप नेता आतिशी, संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले को खारिज किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को खारिज कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने दीक्षित की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, ''मुझे शिकायतकर्ता को बदनाम करने के लिए कोई आरोप नहीं दिखता। यह अदालत संज्ञान लेने से इनकार करती है।'' न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की ओर से समन-पूर्व दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। मानहानि की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आप के दोनों नेता ''जानबूझकर दीक्षित की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं।'' शिकायतकर्ता के अनुसार, एक प्रेसवार्ता में आतिशी और सिंह ने आरोप लगाया कि दीक्षित ने न केवल ''भाजपा से करोड़ों रुपये लिए, बल्कि कांग्रेस ने भी आप को हराने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मिलीभगत की।''

दिल्ली हवाई अड्डे पर पोलैंड के फर्जी वीजा मामले में हरियाणा निवासी एजेंट गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस ने विदेश यात्रा का प्रयास कर रहे लोगों के लिए पोलैंड के फर्जी वीजा की व्यवस्था करने वाले हरियाणा के 36 वर्षीय एक एजेंट को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान गगनदीप सिंह के रूप में हुई है। वह 2021 में दर्ज वीजा धोखाधड़ी के एक मामले में वांछित था। अधिकारी ने बताया कि इसी मामले में एक अन्य एजेंट कुलविंदर की गिरफ्तारी के बाद से वह फरार था। अधिकारी ने कहा कि कुरुक्षेत्र का रहने वाला गगनदीप एक आदतन अपराधी है, जो दिल्ली हवाई अड्डे पर वीजा धोखाधड़ी के दो अन्य मामलों में शामिल था। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (आईजीआई हवाई अड्डा) उषा रागनानी ने कहा, '6 सितंबर, 2021 को पंजाब के दो यात्री चंद्र प्रकाश (22) और सरबजीत (23) पोलैंड के लिए उड़ान भरने के इरादे से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। आव्रजन मंजूरी के दौरान अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट पर पोलैंड का फर्जी वीजा चिपका हुआ पाया।' आईजीआई हवाई अड्डा थाने में बीएनएस की धारा 420 (धोखाधड़ी), 468 (जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेजों को असली दस्तावेजों के तौर पर इस्तेमाल करना) और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ के दौरान दोनों यात्रियों ने खुलासा किया कि उन्होंने कुलविंदर को 3-3 लाख रुपये दिए थे, जिसने पोलैंड के रास्ते पुर्तगाल की उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि कुलविंदर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके जाली वीजा और यात्रा टिकटों का इंतजाम किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच के बाद सितंबर 2021 में कुलविंदर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने कुलविंदर के प्रमुख सहयोगी गगनदीप की पहचान की। उन्होंने बताया कि गगनदीप के ज्ञात ठिकानों पर कई छापे मारे गए, लेकिन वह गिरफ्तारी से बचता रहा। रागनानी ने बताया कि पुलिस को गगनदीप के अमृतसर में होने का पता चला, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गगनदीप ने लगातार पूछताछ के दौरान धोखाधड़ी में अपनी भूमिका कबूल की। उन्होंने बताया कि उसने स्वीकार किया कि वह कई वर्षों से एजेंट के रूप में काम कर रहा था और विदेश में नौकरी के अवसर तलाश रहे व्यक्तियों को ठगने के लिए कुलविंदर के साथ मिलीभगत की थी।

दक्षिण पश्चिम दिल्ली में अवैध रूप से रह रहा बांग्लादेशी पकड़ा गया

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस ने दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के महिपालपुर इलाके में कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान मोहम्मद सदीकुर रहमान (25) के रूप में हुई है, जो इलाज के लिए भारत आया था, लेकिन वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद देश में गैर कानूनी तरीके से रह रहा था। उन्होंने बताया, ''एक गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने होटल बदल-बदल कर रह रहे रहमान को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद अवैध रूप से देश में रहने की बात स्वीकार की।'' अधिकारी ने बताया कि कानूनी औपचारिकताओं के बाद रहमान को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) निर्वासन केंद्र भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि और अधिक अवैध प्रवासियों का पता लगाने और निर्वासित करने के लिए अभियान जारी है।

चोरी के आठ वाहनों के साथ दो चोर पकड़े

नई दिल्ली (एजेंसी)। विकास पुरी थाना पुलिस ने 31 मार्च को दो वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों सुमित कुमार पांडे और मुकुल त्यागी के पास से चोरी की तीन बाइक और पांच स्कूटी बरामद की गई है। विकासपुरी थाने की पुलिस 31 मार्च की रात गश्त पर थी। रात आठ बजे टीम को अरुणोदय अपार्टमेंट के पास विकास पुरी की ओर से आते दो स्कूटी सवार दिखे। पुलिस ने उन्हें रोककर स्कूटी के दस्तावेज मांगे, तो पता चला कि वाहन चोरी का है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उनकी निशानदेही पर विकासपुरी के ई ब्लॉक और ए-ब्लॉक पार्क की झाड़ियों में छिपाकर रखे गए चोरी के अन्य वाहन बरामद हुए।

झपटमारी करने वाले चार बदमाश धरे

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली कैंट थाना पुलिस ने 2 मार्च को एक युवक से झपटमारी करने वाले चार बदमाशों को छह घंटे में गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में दो नाबालिग भी शामिल हैं। आरोपियों हिमांशु और कुणाल पास से मोबाइल फोन, 1200 रुपये नकद और स्कूटी बरामद हुई है। पीड़ित रवि पाल ने बीते मंगलवार को दिल्ली कैंट थाने में झपटमारी की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि स्कूटी सवार चार लोगों ने उससे मोबाइल और पर्स लूट लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो आरोपियों की पहचान हो गई।

विधानसभा के बजट सत्र में सीएजी की छह रिपोर्ट और वार्षिक बजट पेश हुआ: विधानसभा अध्यक्ष

-सदन की कार्रवाई 27 घंटे 56 मिनट चली, सीएजी की रिपोर्टों पर पांच घंटे 32 मिनट तक चर्चा हुई

-ध्यानाकर्षण का नोटिस देकर सदन से नदारद रहे कुलदीप कुमार से आने वाले सत्र में जवाब लिया जाएग

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आठवीं विधानसभा के दूसरे सत्र में सीएजी की छह रिपोर्ट और वार्षिक बजट पेश हुआ। उन्होंने कहा कि विधानसभा का दूसरा सत्र 24 मार्च को शुरू हुआ और 2 अप्रैल को सदन अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र के समापन के बाद गुरुवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन की कुल सात बैठकें हुईं। इन सात बैठकों के दौरान सदन की कार्यवाही 27 घंटे 56 मिनट तक चली। इस दौरान वार्षिक बजट पेश किया गया और पास किया गया, सीएजी की छह रिपोर्ट पेश की गई और कई अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य निपटाए गए। लंबित कार्य निपटाने के लिए सदन की बैठकें दो दिन अर्थात 01 और 02 अप्रैल 2025 तक बढ़ाई गई।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने 25 मार्च 2025 को वार्षिक बजट पेश किया। एक लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए वह दिल्ली सरकार की सराहना करता हैं। इस बजट का उद्देश्य निकट भविष्य में दिल्ली का सर्वांगीण विकास करना है। 26 और 27 मार्च 2025 को बजट पर सात घंटे 13 मिनट तक चर्चा हुई और 36 सदस्यों ने बजट पर चर्चा में भाग लिया, जो अपने आप में उल्लेखनीय है। यह बजट पर चर्चा के लिए समर्पित सबसे लंबी अवधि थी तथा इसमें अधिकतम सदस्यों ने भाग लिया।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि तत्कालीन दिल्ली सरकार के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के वित्त खाते और विनियोग खाते तथा दिल्ली परिवहन निगम और वाहन प्रदूषण पर मुख्यमंत्री ने सीएजी की छह रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत की। 26 सदस्यों ने इन रिपोर्टों पर चर्चा में भाग लिया। चर्चा पांच घंटे 32 मिनट तक चली।

उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से विपक्षी सदस्यों ने इन चर्चाओं में भाग नहीं लिया। मुझे लगता है कि उन्होंने इन रिपोर्टों पर अपने विचार प्रकट करने का एक अच्छा मौका खो दिया, जिन रिपोर्टों को उन्होंने कई वर्षों तक दबा कर रखा था। लोक लेखा समिति (पीएसी) और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (सीओजीयू) का गठन किया जा चुका है और उन्हें उम्मीद है कि समितियां रिपोर्टों की गहन जांच करने के बाद तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश कर देंगी।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन ने एक अप्रैल को दिल्ली के कुछ हिस्सों में कथित रूप से लगातार बिजली कटौती के संबंध में ध्यानाकर्षण के नोटिस पर विचार किया गया। विपक्ष के सदस्य कुलदीप कुमार ने इस संबंध में नोटिस दिया था लेकिन जब इस विषय पर सदन में विचार किया गया, उस समय कुलदीप कुमार सदन में मौजूद ही नहीं थे। इसके अलावा विपक्ष के अन्य सदस्य

भी सदन से नदारद थे। इसके बावजूद सदन में ध्यानाकर्षण को विचार के लिए लिया। कुल आठ सदस्यों ने 58 मिनट तक अपने विचार व्यक्त किए और मंत्री आशीष सूद ने अपना विस्तृत वक्तव्य दिया।

उन्होंने कहा कि ध्यानाकर्षण का नोटिस देने के बाद विचार के समय विधानसभा परिसर में होने के बाद भी कुलदीप कुमार सदन में मौजूद नहीं हुए। यह एक गंभीर मामला है और इसका जवाब आने वाले सत्र में लिया जाएगा।

नाबालिगों के पास कानून के तहत स्वतंत्र अधिकार: हाईकोर्ट

-पीठ ने कहा, कानूनी व्यवस्था को माता-पिता की हरकतों की परवाह किए बिना बच्चों की सुरक्षा करनी चाहिए

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली उच्च न्यायालय में गुरुवार को एक पॉक्सो मामले की सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने कहा कि नाबालिगों के पास कानून के तहत स्वतंत्र अधिकार हैं, जिन्हें सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके माता-पिता ने आपस में ही विवादों को सुलझाने का फैसला किया है।

हाल ही में पारित एक आदेश में पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कानूनी व्यवस्था हर बच्चे के अधिकारों को प्राथमिकता देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि जब माता-पिता उनके साथ खड़े होने में विफल होते हैं, तब भी न्यायपालिका का यह गंभीर कर्तव्य है कि वह उनके अधिकारों की रक्षा करे और कानून के अनुसार न्याय करे। एक नाबालिग लड़की ने अपने पिता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। घटना की सूचना अधिकारियों को न देने के लिए मां के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस बीच पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे बाद में उनके बीच सुलझा लिया गया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने आरोपी पिता की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसमें उसने यह तर्क दिया कि शिकायत बदले की भावना से की गई थी या मां ने अपनी बेटी का इस्तेमाल वैवाहिक विवादों को निपटाने या पैसे ऐंठने के लिए किया था। पीठ ने कहा कि यह मामला एक बहुत ही दुखद और गंभीर स्थिति को उजागर करता है, जहां एक नाबालिग पीड़िता ने कथित तौर पर न केवल अपने माता-पिता के बीच चल रहे विवादों के आघात को सहन किया है, बल्कि अपने ही पिता द्वारा यौन उत्पीड़न के दर्दनाक अनुभव को भी झेला है। पीठ ने कहा कि पीड़िता अपने माता-पिता के बीच कलह और यौन हिंसा के कथित कृत्यों से जूझ रही है।

हैदराबाद केंद्रीय विवि की भूमि नीलामी के विरोध में एबीवीपी ने पर्यावरण मंत्री को सौंपा ज्ञापन

नई दिल्ली (एजेंसी)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के राष्ट्रीय सचिव श्रवण बी. राज और शिवांगी खारवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की चार सौ एकड़ भूमि के अतिक्रमण व नीलामी के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने पर्यावरण मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की, ताकि विश्वविद्यालय की जैव विविधता, वनस्पतियों और जीवों को अतिक्रमण से बचाया जा सके।

इस संदर्भ में अभाविप ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार की मनमानी और छात्रों की आवाज को दबाने के प्रयासों की कड़ी निंदा की। परिषद ने स्पष्ट किया कि शिक्षा और अनुसंधान के लिए समर्पित इस भूमि का निजी कंपनियों को सौंपा जाना न केवल अनुचित और निंदनीय है बल्कि इससे क्षेत्र की पारिस्थितिकी संतुलन को भी गहरी क्षति पहुंचेगी।

यह चार सौ एकड़ भूमि घने हरित क्षेत्र, दुर्लभ वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का आश्रय स्थल है। जहां 734 प्रकार की वनस्पतियां, 220 प्रकार की पक्षी प्रजातियां और संकटग्रस्त भारतीय स्टार कछुआ जैसे जीव पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में

मौजूद 'पीकॉक लेक' और 'बफैलो लेक' स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में सहायक हैं। इसके अलावा हैदराबाद की भूवैज्ञानिक धरोहर का प्रतीक 'मशरूम रॉक' भी इसी भूमि का हिस्सा है।

अभाविप द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कई प्रमुख मांगें सम्मिलित हैं, जिनमें पर्यावरण मंत्रालय द्वारा त्वरित हस्तक्षेप कर जंगलों की कटाई से हो रहे भूमि क्षरण को रोकना, हैदराबाद की पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग मानी जाने वाली समृद्ध वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण सुनिश्चित करना, विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाली संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाना और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना आदि उल्लेखित है। इस क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संपत्ति के रूप में मान्यता देने की मांग भी उठाई गई।

अभाविप के राष्ट्रीय सचिव श्रवण बी. राज ने कहा कि रेवंत रेड्डी सरकार ने अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण शुरू कर दिया है। निजी संस्थाओं को लाभ पहुंचाने के लिए अवैध कार्यों को अंजाम दे रही है। सरकार ने पहले ही बुलडोजर लगाकर शहरी जंगल को नष्ट करने का कार्य आरंभ कर दिया है। जिससे क्षेत्र की पारिस्थितिक संतुलन और पर्यावरणीय स्थिरता को गंभीर खतरा पैदा हो गया है।

बी.राज ने बताया कि आज हमारे प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर इस अवैध अतिक्रमण को तत्काल रोकने और हैदराबाद क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

एबीवीपी की राष्ट्रीय मंत्री शिवांगी खारवाल ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर स्थित प्राकृतिक आवास पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया 'ग्लोबल वार्मिंग' और पर्यावरणीय क्षरण जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि इस हरित क्षेत्र का विनाश न केवल स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेगा, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी गंभीर संकट पैदा करेगा।

शिवांगी खारवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि तेलंगाना सरकार ने विश्वविद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण करने की साजिश रची है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार इस मुद्दे पर संघर्षरत है। छात्र समुदाय की आवाज को बुलंद कर रही है। हम तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे, जब तक कि सरकार विश्वविद्यालय की भूमि और इस जंगल में रहने वाले निर्दोष जीव-जंतुओं को नष्ट करने की अपनी योजना को पूरी तरह छोड़ नहीं देती।

दिल्ली में मुफ्त बस सफर के लिए 2 शर्तें लगाने जा रही रेखा गुप्ता सरकार, रजिस्ट्रेशन भी जल्द

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में मुफ्त बस सफर की सुविधा पर रेखा गुप्ता सरकार दो अहम शर्तें लगाने जा रही है। राजधानी में मुफ्त बस यात्रा का लाभ अब उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जो दिल्ली की निवासी हैं। दूसरी शर्त यह है कि दिल्ली महिलाओं को भी इस सुविधा का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका मतलब है कि यदि अन्य किसी राज्य की महिला दिल्ली में घूमने या अन्य किसी काम से आई है तो उसे बस में सफर के लिए टिकट का भुगतान करना होगा। यदि आप दिल्ली की रहने वाली हैं और रजिस्ट्रेशन करवाकर स्मार्ट कार्ड हासिल नहीं किया है तो आपको भी टिकट खरीदकर यात्रा करनी होगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने के लिए 'स्मार्ट कार्ड' जारी किया जाएगा, जो 'लाइफटाइम' वैध रहेगा। अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार बसों में मुफ्त यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड पाने की इच्छुक महिलाओं के लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। यह कदम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर गुलाबी टिकट योजना के तहत भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। गुप्ता ने कहा था, 'हम महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं... भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम महिलाओं के लिए डिजिटल यात्रा कार्ड शुरू करेंगे, जो उन्हें सरकारी बसों में कभी भी स्वतंत्र रूप से मुफ्त यात्रा करने की सुविधा देगा, जिससे टिकट से जुड़ा 'गुलाबी भ्रष्टाचार' खत्म हो जाएगा।' उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि दक्षता बढ़ाने के लिए टिकट प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल किया जाएगा। गुप्ता ने कहा था कि संपूर्ण प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाएगा और पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा त्रुटिपूर्ण योजनाओं में सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा था, 'हमारा लक्ष्य दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ, विश्वसनीय और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त बनाना है।' 'आप' ने 2019 में भाई दूज के अवसर पर गुलाबी टिकट योजना पेश की थी, जिसके तहत महिलाओं को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है। महिलाओं को गुलाबी टिकट के रूप में एकल यात्रा पास मिलते हैं, जिसमें दिल्ली सरकार प्रति टिकट 10 रुपये की लागत वहन करती है और जारी किए गए कुल टिकट के आधार पर बस कंपनियों को भुगतान करती है। अधिकारियों के अनुसार, भाजपा सरकार के अगले दो से तीन सप्ताह के भीतर स्मार्ट कार्ड पहल पर काम शुरू करने की उम्मीद है। उन्होंने पात्रता मानदंड के बारे में बताया कि स्मार्ट कार्ड केवल दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को जारी किया जाएगा, जिससे उन्हें बिना किसी पाबंदी के कहीं भी, कभी भी यात्रा करने की सुविधा मिलेगी।

पिस्तौल दिखाकर लूटपाट करने वाले दो बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। महरौली थाना पुलिस ने पिस्तौल दिखाकर लूटपाट करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों हैदर अली और मोहम्मद अनस के पास से पुलिस ने एक पिस्तौल और लूटा गया सामान बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक, 25 वर्षीय शिकायतकर्ता बीते बुधवार को अपने चाचा से मिलने छतरपुर पहाड़ी पर जा रहा था। इसी दौरान अंधेरिया मोड़ बस स्टैंड के पास दो बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर उसका पर्स लूट लिया। जांच में आरोपियों की पहचान हैदर और अनस के रूप में हुई। इस पर पुलिस ने बुधवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

पहले चार करोड़ की रंगदारी मांगी, फिर घर पर की फायरिंग

नई दिल्ली (एजेंसी)। जगतपुरी इलाके के कुख्यात बुकी से चार करोड़ की रंगदारी नहीं मिलने पर बुधवार तड़के बाइक सवार दो बदमाशों ने उसके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बुकी और उसके परिजन ने रंगदारी मांगने का आरोप लॉरेंस विश्नोई गैंग पर लगाया है। जगतपुरी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सूत्रों ने बताया कि बीते माह जगतपुरी इलाके में रहने वाले मोनू सरदार को चार करोड़ रुपये की रंगदारी के लिए फोन आया था। आरोपियों ने रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित ने रंगदारी मांगने का आरोप लॉरेंस गिरोह पर लगाया है। रंगदारी का फोन आने के बाद मोनू भारत छोड़कर दुबई भाग गया। उसने मामले में कुछ पुलिसकर्मियों की संलिप्तता का भी आरोप लगाया है। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का सौंपी गई है।

इंस्पेक्टर पर फंसाने का आरोप- मोनू के घर फायरिंग की घटना के बीच उसका और उसके एक जानकार रूबल का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रूबल बातचीत के दौरान मोनू से कह रहा है कि शाहदरा जिले में तैनात एक इंस्पेक्टर उसे जबरन फंसा रहा है। उसके खिलाफ फर्जी केस दर्ज करने की तैयारी है। ऑडियो में मोनू बोल रहा है कि एक पुलिसकर्मी उसे बार-बार फोन कर मिलने के लिए बुला रहा है। सूत्रों ने बताया कि रूबल ने एक शिकायत पुलिस को दी थी। जिसमें कुछ लोगों के नाम थे। पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए मोनू को बुलाया था।

स्पेशल सेल कर रही जांच- रंगदारी मांगने के मामले में मोनू की शिकायत पर जगतपुरी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। सूत्रों की माने तो इस मामले में पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाने के बाद विवाद बढ़ गया। जिसके बाद मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंप दी गई। फिलहाल स्पेशल सेल की टीम सीसीटीवी फुटेज की जांच के साथ रूबल, मोनू सहित कई लोगों की सीडीआर भी खंगाल रही है।

ट्रैफिक जंक्शन प्वाइंट पर लगाए जाएंगे 500 नए कैमरे : सीएम

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी दिल्ली में 500 नए कैमरे लगाए जाने की बात कही है। सीएम ने बताया कि इन कैमरों के जरिए राजधानी में पलूशन के स्तर को बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी। इसके लिए हमने पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिसे उन्होंने विधानसभा में बताया। सीएम ने कहा कि हमने ऐसी योजना बनाई है जिससे कैमरे लगाने में सरकार का एक भी रुपया खर्च नहीं होगा।

सीएम रेखा ने बताया कि दिल्ली में 500 नए कैमरे ट्रैफिक जंक्शन प्वाइंट पर लगाए जाएंगे। जब ये कैमरे इन जंक्शन पर लगेंगे, तो हमें कई तरह के लाभ मिलेंगे। इससे वो व्हीकल (गाड़ियां) दिख जाएंगे जिनका टेन्योर खत्म हो गया है। पलूशन फैलाने वाले व्हीकल के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। इसमें और भी कई तरह की समस्याओं का पता चलेगा। इससे प्रत्यक्ष-

अप्रत्यक्ष तौर पर पूरे वायु प्रदूषण में मदद मिलेगी।

विधानसभा में सीएम रेखा ने बताया कि 500 कैमरों को लगाने में सरकार का एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। इसके लिए हम पीपीपी मॉडल को लेकर आएंगे। हमने एजेंसी को इन्वाइट भी कर लिया है। इसके लिए बिट भी आनी शुरू हो गई है। पीपीपी मॉडल का मतलब- पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। सरकार और निजी क्षेत्र का ऐसा समझौता, जहां दोनों मिलकर किसी पब्लिक योजना या सेवा को देने के लिए अपसी सहयोग करते हैं। इसमें जोखिम और लाभ दोनों आपस में शेयर किए जाते हैं।

आपको बताते चलें कि सर्दियां आते ही राजधानी दिल्ली पलूशन का अड्डा बन जाती है। पराली दहन, गाड़ियों का प्रदूषण, मौसम की बदलती प्रवृत्तियां, लोगों द्वारा आग जलाना, दिवाली-क्रिसमस-न्यूईयर पर पटाखे चलाने जैसे कई कारक जिम्मेदार होते हैं। हालांकि, अन्य मौसमों में भी कमोबेश यही हाल रहता है। और एअर क्वालिटी इंडेक्स अन्य जगहों की तुलना में ऊपर ही बना रहता है।

दिल्ली में बिजली कटौती पर 'आप' कार्यकर्ताओं ने किया भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में हाल ही में बढ़ते बिजली कटौती के संकट को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार को आईटीओ, कालकाजी, आईएसबीटी और बुराड़ी समेत दिल्ली के कई इलाकों में 'आप' कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और 'भाजपा आई - बिजली गई' के पोस्टर लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

अरविंद केजरीवाल ने 'एक्स' पर लिखा, 'बिजली-पानी की भारी किल्लत के बाद अब अस्पतालों से दवाइयां भी गायब हैं। सरकारी अस्पतालों में गरीब लोग इलाज के लिए आते हैं और बिना दवाइयों के उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।'

आईएसबीटी पर विरोध प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने कहा, 'जब से भाजपा की डबल इंजन सरकार आई है, दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में लगातार दो से तीन घंटे के पावर कट हो रहे हैं।'

उन्होंने आरोप लगाया कि 10 साल तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलती थी, लेकिन भाजपा के सत्ता में आने के बाद बिजली संकट ने फिर से सिर उठा लिया है। कुलदीप कुमार ने आगे कहा कि भाजपा की सरकार दिल्ली ही नहीं, बल्कि देश के अन्य 20 राज्यों में भी है, लेकिन वह अब तक किसी भी राज्य में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर पाई।

उन्होंने कहा, 'अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था बनाई थी, लेकिन अब भाजपा सरकार उसे बर्बाद करने का काम कर रही है।'

विधायक कुलदीप कुमार ने चिंता जताई कि अभी गर्मी की शुरुआत में ही दिल्ली के कई इलाकों में लंबे-लंबे पावर कट हो रहे हैं, तो मई-जून की भीषण गर्मियों में बिजली आपूर्ति की स्थिति और खराब हो सकती है।

उन्होंने कहा, 'दिल्ली के लोग इनवर्टर और जनरेटर को भूल चुके थे, लेकिन अब भाजपा सरकार की नीतियों के कारण लोग फिर से इनवर्टर खरीदने को मजबूर हो रहे हैं।' आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था और अब सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। पार्टी ने साफ कहा कि दिल्ली में पावर कट की सरकार नहीं चलेगी। भाजपा को यह सुनिश्चित करना होगा कि दिल्ली के लोगों को 24 घंटे निर्बाध बिजली मिले।

वक्फ बिल पास होने के बाद पहला जुमा, यूपी में चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा

ड्रोन और सीसीटीवी से रखी जा रही नजर

लखनऊ/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव । लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद शुक्रवार की जुमा की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है. राज्य के संवेदनशील जिलों में पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है. सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है. राजधानी लखनऊ समेत संभल, मुरादाबाद, रामपुर, फिरोजाबाद, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली जैसे मुस्लिम बाहुल्य जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है, यहां अर्धसैनिक बल और पुलिस की तैनाती की गई है. प्रदेश में खुफिया विभाग पल-पल की नजर रखे हुए है. गुरुवार की शाम से मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया. आज यानी शुक्रवार को जुमा की नमाज को लेकर विशेष चौकसी बरती जा रही है. मस्जिदों के पास भी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं. राजधानी लखनऊ में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. पूरे शहर को छावनी में बदल दिया गया है. पुलिस के सभी अफसर अलर्ट हैं.

लखनऊ पुलिस छावनी में तब्दील

वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कहीं कोई विरोध प्रदर्शन न हो इसके लिए खुफिया विभाग चौकन्ना बना हुआ है. पुलिस भी हर आने-जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखे हुए है. खास तौर पर लखनऊ में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए शहर की टीले वाली मस्जिद, बड़ा और छोटा इमामबाड़ा समेत 61 हाट स्पाट बनाए गए हैं, जिनपर सीसीटीवी और ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी.

संभल से लेकर वाराणसी तक पुलिस की निगरानी

प्रदेश के अलीगढ़, मेरठ, बरेली, मुजफ्फरनगर, शामली, आगरा, संभल, मथुरा, फिरोजाबाद, वाराणसी, प्रयागराज जिलों पर भी पुलिस की विशेष निगरानी है. वक्फ बिल के पास होने के बाद जुमा की

पहली नमाज को लेकर इन जिलों में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. अलग-अलग शहरों को कई-कई सेक्टरों में बांटा गया है. मेरठ जिले को 4 जोन और 32 सेक्टरों में बांटा गया है. अतिसंवेदनशील संभल जिले में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया गया है.

सोशल मीडिया पर रखी जा रही नजर

पुलिस प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है. पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की भडकाऊ पोस्ट करने वालो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के अफसर लगातार इमाम, मौलवी और धर्मगुरुओं से संपर्क में बने हुए हैं. लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है.

संक्षिप्त डायरी

प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए समय से पूरी की जाएं सभी तैयारियां: मुख्यमंत्री

वाराणसी/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सर्किट हाउस सभागार में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे में होने वाले सभी कार्यक्रमों की तैयारियों को समय से पूरा किए जाने और प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन-शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं की सभी तैयारी करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने नमो घाट पर कतिपय स्थानों पर जमीन के धंसने की घटना का संज्ञान लिया। इसके गुणवत्ता की जांच कराते हुए शीघ्र मरम्मत कराने और वरुणा रिवर फ्रंट के सुंदरीकरण कार्यों के संबंध में शीघ्र ठोस कार्ययोजना बनाकर कार्य किए जाने का निर्देश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को सबसे पहले प्रधानमंत्री के प्रस्तावित सभास्थल राजा तालाब के मेहंदीगंज पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किए जाने के साथ ही अन्य सभी तैयारी भी समय से पहले पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। बोले कि सभा स्थल पर आने वालों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहां पेयजल, छाया, मोबाइल टॉयलेट, ओआरएस पैकेट आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। बैठक में कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया।

लखनऊ में घर का सपना होगा पूरा, अनंत नगर आवासीय योजना का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी

लखनऊ/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव । उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा अनंत नगर आवासीय योजना के अंतर्गत शुक्रवार को पंजीकरण प्रक्रिया का शुभारंभ सीएम योगी के हाथों होने जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मोहान रोड स्थित अनंत नगर आवासीय योजना को कुल 785 एकड़ में 10 हजार करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है। इस योजना के जरिए विभिन्न आय वर्गों के लोगों को भूखंड प्राप्त करने का अवसर मिलेगा जिसमें मुख्य तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्गों को तरजीह दी जाएगी। अनंत नगर योजना के अंतर्गत भूखंड पाने के लिए आवेदन करने व अधिक जानकारी के लिए एलडीए की वेबसाइट तथा टोल फ्री नंबर 180018005000 पर कॉल किया जा सकता है। इसी के साथ ही, एलडीए के विभिन्न आवासीय परियोजनाओं से निर्माण व विकास से संबंधित कार्यों को गति देने तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 147.85 करोड़ से अधिक कीमत के रिक्त फ्लैट्स की बिक्री का मार्ग प्रशस्त करने के लिए नई स्ट्रैटेजी अपनाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। प्रक्रिया के अंतर्गत श्रवण, आद्रा, अनुभूति, सोपान एन्क्लेव फेज-2, रश्मि लोक तथा मृगशिरा अपार्टमेंट में रिक्त फ्लैट्स को बेचने का मार्ग प्रशस्त होगा। सीएम योगी के विजन को मिशन मानकर लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा मोहान रोड पर विकसित की जा रही अनंत नगर आवासीय योजना कई मायनों में विशिष्ट होगी। यहां सभी आर्थिक वर्गों के लोगों के लिए भूखंड पाने का अवसर होगा मगर विशेष रूप से लोअर इनकम ग्रुप्स के लोगों को यहां तरजीह दी जाएगी। यह योजना उत्तर प्रदेश की पहली एडु-टेक सिटी के समीप स्थित होगी इसलिए भविष्य में यह आर्थिक, व्यापारिक व सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनेगी। इस योजना के जरिए करीब एक लाख तक की जनसंख्या को सुरक्षित व व्यवस्थित आवासीय क्षेत्र उपलब्ध कराने की योगी सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जाएगा। अनंत नगर योजना के हर खंड में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, शॉपिंग सेंटर, बारात घर और वेंडिंग जोन होंगे। योजना को कुल 8 खंड में विकसित किया जाएगा। एलडीए द्वारा मोहनलालगंज में 1197.98 एकड़ में प्रस्तावित वेलनेस सिटी तथा मोहनलालगंज में ही 1696.77 एकड़ में प्रस्तावित आईटी सिटी के अंतर्गत चिह्नित ग्रामों में भूमि अधिग्रहण के लिए आंकलन की प्रक्रिया भी जारी है जिसे जल्द ही पूरा किया जा सकता है।

वीरता के साथ अब विकास का भी इतिहास रच रहा बुंदेलखंड

बुंदेलखंड/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव । शौर्य और संस्कार की धरती। अपनी वीरता के इतिहास के लिए विख्यात बुंदेलखंड की धरा आने वाले समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से विकास का इतिहास रचने जा रही है। अक्सर सूखे के लिए जाने जाना वाला बुंदेलखंड भविष्य में अपनी हरियाली के नाते जाना जाएगा। यहां की बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजनाएं, खेत तालाब योजना के तहत बनाए गए तालाब इसका जरिया बन रहे हैं। कृषि के साथ ही बुंदेलखंड औद्योगिक प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है।

यूपी के 10 फीसद क्षेत्रफल वाले बुंदेलखंड की कृषि में हिस्सेदारी सिर्फ 5.5 फीसद

उल्लेखनीय है कि बुंदेलखंड में सात जिले (चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर) शामिल हैं।

करीब 69 हजार वर्ग किलोमीटर में विस्तृत बुंदेलखंड का रकबा उत्तर प्रदेश के कुल रकबे का करीब 10 फीसद है। यहां दलहन और तिलहन की फसलों की खेती की अच्छी संभावना है। इसी लिए सरकार यहां दलहन ग्राम योजना भी चला रही है। साथ ही पूरे बुंदेलखंड में मिशन मॉड में प्राकृतिक खेती की प्रोत्साहन पर भी सरकार का पूरा फोकस है।

उल्लेखनीय है कि अमूमन सूखे का सामना करने वाले बुंदेलखंड की कृषि उत्पादन में हिस्सेदारी सिर्फ 5.5 फीसद है। उत्पादन के इस अंतर की भरपाई के लिए सरकार बुंदेलखंड में सिंचन क्षमता में लगातार विस्तार कर रही है। साथ ही विश्व बैंक की मदद से चार हजार करोड़ की लागत से छह वर्ष तक चलने वाली उत्तर प्रदेश ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग (यूपी एग्रीज) योजना में बुंदेलखंड के सभी जिलों को शामिल कर सरकार यहां के खेतीबाड़ी का भी कायाकल्प करने जा रही है। फिलीपींस के मनीला स्थित स्थित इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंटीट्यूट की वाराणसी शाखा भी इस परियोजना में बतौर एक पार्टनर शामिल है। योजना के तहत क्लस्टर खेती को बढ़ावा देने के साथ डिजिटल और वित्तीय इकोसिस्टम को मजबूत किया जाएगा। साथ ही किसानों को सघन ट्रेनिंग दी जाएगी।

डिफेंस कॉरिडोर, बीडा, फार्मा पार्क से उद्योगों का भी केंद्र बनेगा बुंदेलखंड

योगी सरकार की पहल पर हो रहा बुंदेलखंड के औद्योगिकीकरण इसे उत्तर प्रदेश का ही नहीं देश के बड़े इंडस्ट्रियल हब में शुमार करेगा। डिफेंस कॉरिडोर, ललितपुर में बनने वाला फार्मा पार्क, कानपुर और झांसी के बीच प्रस्तावित देश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे किनारे बनने वाले औद्योगिक गलियारे, ललितपुर में बन रहा फार्मा पार्क इसका जरिया बनेंगे।

कनेक्टिविटी से मिलेगी तरक्की को रफ्तार

विकास कार्य को गति देने में कनेक्टिविटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण का यही मकसद है। उसके अलावा सरकार सभी एक्सप्रेस वे को आपस में जोड़ने का काम भी करने जा रही है। इससे बुंदेलखंड प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों से भी तेजी से जुड़ जाएगा। यहां के उत्पादों को कहीं भी कम समय में तेजी से भेजना संभव होगा।

शीघ्र ही सात जिलों वाले बुंदेलखंड में होंगे तीन एयरपोर्ट

बुंदेलखंड में बेहतर एयर कनेक्टिविटी सोने पर सुहागा होगी। चित्रकूट में एयरपोर्ट बन चुका है। ललितपुर और झांसी में बन रहा है। इनके बनने पर महज सात जिलों वाले बुंदेलखंड में तीन एयरपोर्ट हो जाएंगे। इससे यहां के पर्यटन उद्योग को भी खासी तेजी मिलेगी। खासकर ऐतिहासिक पर्यटन को। यहां के कालिंजर जैसे किले, चंदेलकालीन तालाबों की अदभुत श्रृंखला, चित्रकूट जहां भगवान श्रीराम ने पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण समेत अपने वनगमन के दौरान सर्वाधिक समय गुजारे थे। यहीं पर राम और भरत का मिलन भाई-भाई के प्रेम की मिसाल बन गया। प्रयाग महाकुंभ के दौरान जिस तरह चित्रकूट में पर्यटकों का उलट प्रवाह हुआ, वह चित्रकूट के बढ़ते आकर्षण का सबूत है। योगी सरकार उसी अनुसार अयोध्या से चित्रकूट तक के राम वनगमन मार्ग को सजा रही है। चित्रकूट में बना रोपवे इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहा है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने राज्यभर में कुट्टू के आटे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी अभियान शुरू

देहरादून/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने राज्यभर में कुट्टू के आटे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी अभियान शुरू किया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि रोज इस अभियान की समीक्षा की जाती है। अधिकारियों के फीडबैक के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाती है। इस अभियान का उद्देश्य मिलावटी और असुरक्षित कुट्टू के आटे की बिक्री को रोकना और जनता को सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। 03 अप्रैल को खाद्य सुरक्षा विभाग ने राज्य के विभिन्न जनपदों में कुट्टू के आटे के 7 नमूने और पांच अन्य व्रत में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए। इन नमूनों को प्रयोगशाला भेजा गया और जांच में 2 कुट्टू के आटे के नमूने असुरक्षित पाए गए। इसके बाद, खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को न्यायालय में वाद दायर करने के निर्देश दिए और मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि हम सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों का सेवन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। कुट्टू के आटे की जांच के परिणामों को गंभीरता से लिया गया है और असुरक्षित पाए गए नमूनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। काफी हद तक विभाग ने सभी जनपदों में अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की है। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा, ताकि दूषित और मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री को पूरी तरह रोका जा सके। कुमाऊं मंडल में भी छापेमारी अभियान जारी है। एफडीए की टीम ने उपायुक्त डा. राजेंद्र कांडपाल के निर्देशन में विभिन्न जनपदों में छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के तहत दुकानों पर छापेमारी की गयी। हर जनपद में दो टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों ने तीन दर्जन से अधिक सैंपल एकत्रित किये हैं, जिन्हें जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा गया है। ऊधमसिंह नगर से लिए गए एक सैंपल में कीड़े पाए गए। देहरादून जिले में भी विशेष निगरानी अभियान चलाया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने राजपुर रोड, कैनाल रोड, हाथीबडकला, यू कैंट रोड और डाकरा बाजार में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इन प्रतिष्ठानों में खुला या पैक्ड कुट्टू का आटा विक्रय हेतु उपलब्ध नहीं था। हालांकि, विभाग लगातार निगरानी बनाए रखेगा और किसी भी मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थों की खरीदारी करते समय सतर्क रहें। किसी भी संदिग्ध खाद्य सामग्री की जानकारी तुरंत विभाग को दें, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम इस अभियान के दौरान सभी प्रतिष्ठानों पर निगरानी बनाए रखेगी और सुनिश्चित करेगी कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ ही उपलब्ध हो।

सीएम धामी के कुशल नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्तराखण्ड में एक साल में बनी 814 किमी ग्रामीण सड़कें

देहरादून/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हाल में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान 814 किमी लंबी सड़कों का निर्माण किया गया। राज्य की प्रगति को देखते हुए भारत सरकार ने योजना के तीसरे चरण में स्वीकृत 09 पुलों के निर्माण के लिए भी बजट जारी कर दिया है। उत्तराखण्ड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 900 करोड़ के वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष लगभग रू0 933 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है, जो विगत वर्ष 2023-24 में किये गये व्यय से रू0 133 करोड़ अधिक है। इसी प्रकार भौतिक उपलब्धि में भी वित्तीय वर्ष 2024-25 में 814 किमी लम्बाई में मार्गो का निर्माण किया गया है, जो वर्ष 2023-24 की उपलब्धि 206 किमी अधिक है। इस बीत गत वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पीएमजीएसवाई -3 के अन्तर्गत 09 सेतुओं के निर्माण के लिए 40.77 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। इधर, विभाग ने एमजीएसवाई-4 के तहत 1490 सड़क विहीन बसावटों को चिन्हित कर प्रथम चरण में लगभग 8500 किमी सड़कों निर्माण का सर्वे पूरा करते हुए, डीपीआर पर काम शुरू कर दिया है। विभाग ने कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर जारी निदेशों के अतिरिक्त एक विशेष निरीक्षण एप तैयार किया है। एप के माध्यम से फील्ड अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों को नियमित रूप से अंकित किया जा रहा है, जिससे उच्चाधिकारियों द्वारा मार्गों की गुणवत्ता का अनुश्रवण करना सुलभ हो गया है। भारत सरकार स्तर पर भी इस पहल की सराहना करते हुए अन्य राज्यों को इसे अपनाने को कहा है। विदित है कि सड़क विहीन गांवों के लिए केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की गई थी। प्रथम तीन चरणों में न्यूनतम 500 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम करीब- करीब पूरा हो चुका है।

महाकुम्भ के आयोजन स्थल को बताया था वक्फ की जमीन, पीएम मोदी ने मनमानी पर लगायी लगाम- सीएम योगी

भू माफिया बन गया वक्फ बोर्ड, यूपी में माफियागीरी नहीं चलेगी- योगी आदित्यनाथ

प्रयागराज/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव । सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ की तैयारी के दौरान वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि कुंभ की भूमि उनकी है। यह माफिया बोर्ड बन गया था। लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी मनमानी पर लगाम लगा दी है। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ बोर्ड से संबंधित एक महत्वपूर्ण अधिनियम लोकसभा में पारित हो चुका है और जल्द ही राज्यसभा में भी पास होगा, जिससे यह केवल कल्याणकारी कार्यों तक सीमित रहेगा। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की माफियागीरी नहीं चलेगी, यहां के माफिया को तो हम पहले ही विदा करवा चुके हैं।

श्रृंगवेरपुर का विकास भगवान राम और निषाद राज की मित्रता का प्रतीक- सीएम योगी

सीएम योगी ने श्रृंगवेरपुर में भगवान श्री राम और निषाद राज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि निषाद राज पार्क भगवान राम व निषाद राज की मित्रता का भव्य स्मारक है। सीएम योगी ने पार्क का निरीक्षण किया और कहा कि हजारों वर्ष पहले इसी पावन धरा पर भगवान राम ने कदम रखा था। निषाद राज ने मित्रता का धर्म निभाते हुए भगवान राम को गंगा पार कराई और चित्रकूट तक उनका साथ दिया।

महाकुंभ ने प्रयागराज को दी वैश्विक पहचान- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ 2025 की सफलता प्रयागराज की नई पहचान का आधार बना है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज पर मां गंगा की असीम कृपा है। महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए। दुनिया का कौन सा देश और भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा था, जो यहां नहीं पहुंचा? त्रिवेणी संगम में स्नान कर हर कोई पुण्य का भागीदार बना। उन्होंने कहा कि अब प्रयागराज को वाराणसी के बगल में बताने की जरूरत नहीं, यह अपनी वैश्विक पहचान बना चुका है। सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज का अर्थ है महामिलन स्थल। यहां गंगा-यमुना-सरस्वती का मिलन है, तो भगवान राम और निषाद राज का मिलन भी है।

महाकुंभ की सफलता सनातन धर्म की शक्ति का प्रतीक- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ की सफलता सनातन धर्म की शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इतना भव्य आयोजन केवल राम भक्त और राष्ट्रनिष्ठ लोग ही कर सकते हैं। यह मां गंगा, भगवान राम, निषाद राज और द्वादश माधव की कृपा का परिणाम है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में योगदान देने वाले प्रशिक्षित गाइड, नाविकों और होम स्टे संचालकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सीएम योगी ने कहा कि

महाकुम्भ के बहाने प्रयागराज का चौतरफा विकास हुआ है।

पिछली सरकारें प्रयागराज की पहचान मिटाने और माफियाओं को बढ़ावा देने में लगी थीं- सीएम योगी

सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि महाकुंभ की तैयारी के दौरान वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि कुंभ की भूमि उनकी है। यह माफिया बोर्ड बन गया था। लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी मनमानी पर लगाम लगाई। सीएम ने पीएम मोदी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है कि महाकुंभ भव्य और दिव्य हुआ।

वर्षा जल संरक्षण और भू जल स्तर को बढ़ाने के लिए उठाये जाएं प्रभावी कदम : सीएम धामी

देहरादून/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में पेयजल और जलागम की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आगामी 30 साल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में जलापूर्ति के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। इसके साथ ही वर्षा जल संरक्षण और भू जल स्तर को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाएं। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जल स्रोतों, नदियों और जल धाराओं के पुनजीर्वीकरण के लिए जन सहयोग लिया जाए। इस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के सुझाव लेकर उनको आगे की कार्ययोजनाओं में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि पेयजल, जल संचय और जल संरक्षण के लिए आगामी 10 साल और आगामी 30 साल की आवश्यकताओं के हिसाब से अलग-अलग ठोस प्लान बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य की अंतिम सीमा तक गंगा का जल पूर्ण रूप से पीने लायक हो इस दिशा में कार्य किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंगा की सहायक नदियों पर एसटीपी लगाने के कार्य किये जाएं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गंगा नदी की स्वच्छता के लिए जनसहयोग और सुझाव लिये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत लगे कनेक्शनों से लोगों को नियमित जलापूर्ति हो, इसके लिए पुराने जल स्रोतों के पुनजीर्वीकरण के साथ ही नये जल स्रोत भी चिन्हित किये जाएं, जिससे गर्मियों में पेयजल की समस्या न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी के स्टोरेज टैंक और पेयजल टेंकर की नियमित सफाई की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में पेयजल की गुणवत्ता की समय-समय पर टेस्टिंग की जाए। उन्होंने कहा कि पेयजल की गुणवत्ता के सभी मानक सही पाए जाने पर प्राकृतिक जल स्रोतों से निकलने वाले पानी के अधिक उपयोग के लिए लोगों को जागरूक किया जाए।

नई पेयजल लाइन बिछने पर सड़क की खुदाई की शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों द्वारा समन्वय बनाकर कार्य किये जाएं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि विभिन्न विभागों की जिन परिसंपत्तियों का उपयोग नहीं हो रहा है, उनकी समीक्षा कर सही उपयोग किया जाए।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड रजतोत्सव वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस युवा प्रदेश मे कार्य करने की अपार संभावनाएं हैं। हमें नवाचारों और बेस्ट प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान देना है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि राज्य में कुछ ऐसी योजनाएं बने, जो अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल बने। उत्तराखण्ड में "सारा" के तहत हो रहे कार्यों की भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय ने भी सराहना की है। इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, उत्तराखण्ड अवस्थापना अनुश्रवण परिषद् के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, आर.मीनाक्षी सुदंरम, सचिव शैलेश बगौली, रणवीर सिंह चौहान, विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते, परियोजना निदेशक जलागम नीना ग्रेवाल, अपर सचिव हिमांशु खुराना एवं सबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

4 आईएएस अधिकारियों को शासन ने सौंपी चार धाम यात्रा को लेकर अहम जिम्मेदारी

देहरादून/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव । उत्तराखण्ड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होने वाला है। जिसके दृष्टिगत पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग समेत अन्य संबंधित विभाग भी तैयारी में जुटे हुए हैं। ताकि उत्तराखण्ड चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इसी क्रम में शासन ने अधिकारियों को यात्रा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखण्ड शासन के पर्यटन अनुभाग ने चारधाम यात्रा मार्गों और धामों की स्थलीय व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने हेतु वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नामित किया है। मुख्य सचिव के निदेर्शानुसार चारधाम यात्रा के प्रमुख धामों की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए निम्नलिखित सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

गंगोत्री धाम झ्र सचिव बी०वी०आर०सी० पुरुषोतम निरीक्षण करेंगे।

यमुनोत्री धाम झ्र सचिव नीरज खैरवाल को जिम्मेदारी दी गई है।

बद्रीनाथ धाम झ्र सचिव आर० राजेश कुमार यात्रा व्यवस्था की देखरेख करेंगे। केदारनाथ धाम झ्र सचिव युगल किशोर पन्त निरीक्षण करेंगे।

यह सभी अधिकारी देहरादून से सड़क मार्ग के माध्यम से संबंधित धामों तक पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। इसके तहत सड़कों की स्थिति, पार्किंग सुविधाएं, तीर्थयात्रियों के लिए आवश्यक सेवाएं, आपदा प्रबंधन योजना और चिकित्सा व्यवस्थाओं सहित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का मूल्यांकन किया जाएगा। सचिवों द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षण के आधार पर यात्रा व्यवस्थाओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार

की जाएगी, जिसे 11 अप्रैल को पूर्वान्ह 11:30 बजे मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने हेतु आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। उत्तराखण्ड में चारधाम यात्रा हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। इसे देखते हुए सरकार यात्रा मार्गों को बेहतर बनाने, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को दुरुस्त करने में जुटी है।

भतीजी से जबरन संबंध बनाने की कोशिश का आरोप

चाचा ने भतीजी को पंचायत में पीटा, आरोपी चाचा ने भी लगाए आरोप, FIR दर्ज

वैशाली। बिदुपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। चकसिकंदर गांव में एक चाचा ने अपनी भतीजी से जबरन संबंध बनाने की कोशिश की। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो उसे पंचायत में बुलाकर बेरहमी से पीटा गया। घटना का वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है।पति को मिसगाइड कर तुड़वा दिया रिश्तापीड़िता ज्योति कुमारी (21) ने बताया कि उसके दो चाचा विभीषण महतो (43) और शत्रुघ्न महतो (41) ने पहले उसके पति मिथिलेश कुमार महतो (25) को फेसबुक मैसेंजर पर गलत संदेश भेजकर शादी में विवाद पैदा किया। इस साजिश के चलते 3 साल पहले हुई शादी के शुरूआती 2 महीने में उसका वैवाहिक रिश्ता खराब हो गया।ववाद होने पर पीड़िता की मां ने ससुराल वालों पर [illegible] करने की धमकी दी। इसके बाद पति ने 7 महीने ज्योति को साथ रखा। इस दौरान पीड़िता की चचेरी बहन ने पति को मिसगाइड कर रिश्ता तुड़वा दिया। पति के छोड़ने के बाद पीड़िता करीब 2 साल से अपने मायके में ही रह रही है।पीड़िता के अनुसार, मायके आने के बाद चाचा ने उस पर अनैतिक संबंध बनाने का दबाव डालना शुरू कर दिया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी चाचा धमकाने लगे। 1 अप्रैल 2025 की सुबह चाचा ने गांव में पंचायत बुलाई। इस दौरान पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि, सरपंच और अन्य ग्रामीणों के सामने पीड़िता को उसके चाचा सहित कुछ लोगों ने बेरहमी से पीटा। पीड़िता की मां संजू देवी (43) और बहन रौशनी कुमारी जब इस घटना का वीडियो बनाने लगीं, तो उन्हें भी पीटा गया। इस दौरान मुखिया प्रतिनिधि अनिरुद्ध कुमार ने भी आरोपी का साथ दिया। वह पीड़िता को बिजली के खंभे से बांधकर पीटने की बात कहता रहा। आसपास मौजूद ग्रामीण भी पीड़िता की मदद के लिए आगे नहीं आए।पीड़िता और उसके परिवार को धमकीपीड़िता ने बताया कि जब वह इस घटना की शिकायत लेकर थाने पहुंची, तो मुखिया प्रतिनिधि अनिरुद्ध कुमार ने दबाव डालकर केस दबाने की कोशिश की। वहीं, आरोपी चाचा विभीषण महतो ने अपने खिलाफ दर्ज कराए गए केस वापस लेने का दबाव डाला। आरोपी चाचा ने पीड़िता के पिता भरत महतो और इकलौते भाई आयुष महतो (13) को अगवा करने की धमकी दी है। पीड़िता के पिता भरत महतो (45) सिलीगुड़ी में रहकर वहां की किसी कंपनी में काम करते हैं।माता और बहन के साथ पीड़िता की फोटोहालांकि, भतीजी पर संबंध बनाने का दबाव बनाने के आरोपों को चाचा विभीषण ने खारिज किया है। उन्होंने बताया कि मेरे बड़े भाई की लड़की की शादी होने वाली है। वहां ज्योति गलत गलत मैसेज भेजकर रिश्ते तुड़वाने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले भी उसने दो रिश्ते तुड़वा दिए हैं। मेरी भतीजी की फोटो को एडिट करके वायरल कर रही थी। इसी को लेकर पंचायत बुलाई गई थी।आरोपी चाचा विभीषण का कहना है कि पंचायत में उससे पूछताछ की जा रही थी। तभी दौरान गाली गलौज करने लगी। इसी को लेकर बड़े भाई शत्रुघ्न महतों से बर्दाश्त नहीं हुआ और लड़की पर हाथ चला दिया।शादी जुड़वाने के आरोपों को नकारापीड़िता की रिश्ते तुड़वाने को लेकर आरोपी चाचा ने कहा कि हम उसके ससुराल वालों या पति को जानते तक नहीं हैं। किसी प्रकार की मैसेज मेरे द्वारा नहीं भेजा गया है। यदि भेजा गया है तो पुलिस डेटा निकाल कर मुझ पर करवाई कर सकती है।वहीं, सरपंच प्रतिनिधि अरविंद कुमार पासवान ने बताया कि वह लोगों का सामाजिक पंचायत था। मुझे किसी पक्ष ने पंचायत में नहीं बुलाया गया था। जानकारी मिली है कि मारपीट हुई है।पुलिस ने कहा- दोषियों को नहीं बख्शा जाएगापंचायत में पिटाई के अगले दिन 2 अप्रैल को पीड़िता ने बिंदुपुर थाने में शिकायत दी। पीड़िता ने अपने आवेदन में चाचा विभीषण महतो, शत्रुघ्न महतो, आदित्य कुमार, पूजा देवी, प्रियंका कुमारी और अनिता देवी पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। थाना अध्यक्ष अरुण कुमार ने आवेदन की जांच करने के बाद मारपीट और छेड़खानी, कपड़े फाड़ने वाली धारा में एफआईआर दर्ज किया है।इस मामले में बिदुपुर थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा कि पीड़िता ने आवेदन के साथ पिटाई का वीडियो भी पुलिस को सौंपा है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी आरोपों की जांच करने के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है।

मधेपुरा में महिला और युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा

मधेपुरा । के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर गांव में बुधवार रात एक 45 साल की महिला को ग्रामीणों ने कथित रूप से 24 साल के के युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने युवक की पिटाई कर दी और अगले दिन पंचायत बुलाकर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में महिला के ससुर ने सिंहेश्वर थाना में आवेदन दिया है। उनके अनुसार शंकरपुर थाना क्षेत्र के मौरा कवियाही वार्ड-12 निवासी युवक एक अप्रैल से उनके घर पर रह रहा था और उनकी बहू के साथ अवैध संबंध बना रहा था। बुधवार रात ग्रामीणों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया, जिसके बाद डायल-112 पर सूचना दी गई। घटना के दौरान युवक के साथ मारपीट भी की गई। युवक ने प्रेम प्रसंग की बात से किया इनकाररात में महिला और युवक ने ग्रामीणों के सामने शादी करने की इच्छा जताई, जिसका वीडियो भी ग्रामीणों ने बना लिया।

वाल्मीकिनगर के जंगल में लगी आग, रिहायशी इलाके पहुंचे वन्यजीव

बेतिया। वाल्मीकिनगर के जंगल में लगी आग के चलते वन्यजीव अब तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं। बुधवार रात हवाई अड्डा चौक स्थित महेश शाह के घर में विशालकाय कोबरा सांप दिखाई देने से हड़कंप मच गया। जैसे ही घरवालों की नजर सीढ़ी पर बैठे कोबरा पर पड़ी, सभी डर गए और तुरंत वन विभाग को सूचना दी। कुछ ही देर में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और विशेष उपकरणों की मदद से सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। जंगल की आग से बढ़ रहा संकट बुधवार को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के प्रमंडल-2 में त्रिवेणी कैनाल के किनारे जंगल में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने उसे बुझाया, लेकिन तब तक करीब 6 एकड़ सदाबहार जंगल जलकर राख हो चुका था। वन विभाग की तत्परताआग की सूचना मिलते ही रेंजर श्रीनिवासन नवीन के नेतृत्व में वन कर्मियों और फायर वॉचरों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया।आग लगने के कारणों की जांच जारीवन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आग लगने के सटीक कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। हालांकि, यह संदेह है कि आग गर्मी, मानवीय लापरवाही या जंगल में फेंकी गई जलती चीजों के कारण लगी हो सकती है।वन्यजीवों का इंसानी बस्तियों की ओर रुखगर्मी और जंगल की आग के कारण वन्यजीव अब सुरक्षित स्थानों की तलाश में रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और जंगल की आग से वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, जिससे वे इंसानी बस्तियों की ओर आने को मजबूर हो रहे हैं।

धुआं निकलने पर यात्रियों ने दी आवाज, ड्राइवर नहीं रुका

मोतिहारी। में बुधवार की रात सुपौल से दिल्ली जा रही शिव महिमा कंपनी की बस में आग लग गई। पिपरा कोठी थाना क्षेत्र के बंगरी ओवर ब्रिज के पास यह घटना हुई। इस हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं। पुलिस घटना की जांच कर रही है। तकनीकी खराबी के चलते लगी आग जानकारी के अनुसार, बस में तकनीकी खराबी के चलते क्लच प्लेट में आग लग गई। यात्रियों ने बताया कि सुपौल से चलने के बाद बस में दो बार खराबी आई थी। ड्राइवर ने इसे नजरअंदाज किया और बस चलाता रहा। बस से धुआं निकलता देख यात्रियों और अन्य वाहन चालकों ने ड्राइवर को रोकने को कहा, लेकिन उसने बस नहीं रोकी। करीब 3 किलोमीटर तक बस चलने के बाद आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान यात्रियों ने जल्दी बस से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आईं है और कुछ के हाथ झुलस गए हैं। सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। यात्रियों का सारा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू बस में आगजनी की सूचना मिलते ही पिपरा कोठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फौरन फायर ब्रिगेड को बुलाया गया।

इसके बाद दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बस कंपनी ने यात्रियों के लिए दूसरी बस का इंतजाम किया और उन्हें सुरक्षित गंतव्य के लिए रवाना किया।

डीएम और एसपी के रक्सौल पहुंचने पर सड़कों से हटा जाम, तैनात दिखे जवान

रक्सौल। बुधवार को डीएम सौरभ जोरवाल और एसपी स्वर्ण प्रभात के अचानक रक्सौल पहुंचने से शहर से जाम गायब हो गया। जिस सड़क पर दिन में हमेशा बाइक व अन्य वाहन खड़े दिखते थे। दुकान सजी रहती थी। वहां एक भी वाहन नहीं दिखा। अधिकारियों के आगमन से पहले स्थानीय प्रशासन ने व्यवस्था सुधार दी। चौक-चौराहों पर पुलिस तैनात कर दिए थे। कोईरिया टोला से कस्टम कार्यालय, रेलवे स्टेशन रोड, आश्रम रोड और आर्य समाज रोड जैसे व्यस्त मार्गों पर जाम नहीं दिखा। इसे देख लोगों को आश्चर्य भी हुआ। लोगों का कहना था कि क्या व्यवस्था सिर्फ डीएम व एसपी के लिए ही होगा या आम लोगों के लिए भी। डीएम व एसपी को तो यहां प्रतिदिन आना चाहिए। जिससे लोगों को कम से कम जाम की समस्या से जूझना तो नहीं पड़ेगा। लोगों ने बताया कि आम दिनों में रक्सौल की सड़कों पर बेतरतीब बाइक पार्किंग, ई-रिक्शा की अव्यवस्थित खड़ी और फुटपाथी दुकानों के कब्जे से जाम लगा रहता है। लेकिन बुधवार को यातायात पूरी तरह सुचारू रहा।

दहेज के लिए पत्नी की हत्या का आरोप

मोतिहारी। के पताही थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान 26 साल की किरण देवी के रूप में हुई है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका की मां ने बताया कि दो साल पहले किरण की शादी राम परीक्षण महतो से हुई थी। ससुराल वाले दहेज में वॉशिंग मशीन और सीकरी की मांग करते थे। इस बात को लेकर किरण के साथ अक्सर मारपीट की जाती थी। पति का भाभी के साथ अवैध संबंध परिजनों का आरोप है कि मृतका के पति का भाभी के साथ अवैध संबंध था। इसी कारण वह किरण को पसंद नहीं करता था। मायके पक्ष का कहना है कि पति, सास और घर के अन्य सदस्यों ने मिलकर किरण का गला घोंट दिया। फिर शव को कमरे में बिछावन पर चादर से ढक दिया।

'मेरे पिता कुछ नहीं थे,फिर भी बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया

पटना। में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को एक बार लालू यादव से पूछना चाहिए। लालू के बगैर तेजस्वी की कोई पहचान नहीं है। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। मेरे पिता कुछ नहीं थे, इसके बाद भी बीजेपी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के वायरल वीडियो पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों के पास खाने और दिखाने के दांत अलग-अलग होते हैं। विपक्ष के लोग एक स्टैंड पर नहीं रहते हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ बोलते हैं। भ्रम फैलाया जा रहा है। वक्फ पर वर्ष 2010 में जब लालू यादव भाषण दे रहे थे, उस समय सदन में सोनिया गांधी भी मौजूद थीं। मैं किशनगंज से आता हूं। जहां सबसे ज्यादा समझदार मुसलमान हैं। मुस्लिम समाज के लोग मुझे वोट करते हैं। मैं रमजान के महीने में चुनाव जीतता हूं।दिलीप जायसवाल ने आगे कहा कि 6 अप्रैल का बीजेपी का स्थापना दिवस है। इस मौके पर राज्य में एक सप्ताह तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी जिला मुख्यालय में 70 साल की यात्रा की प्रदर्शनी लगेगी। कार्यालय को भव्य तरीके से सजाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। बूथ स्तर पर पार्टी के झंडे लगाए जाएंगे।

सऊदी अरब में फंसा अमीरुद्दीन 14 साल बाद लौटा घर

रऊद की पहल पर इंडियन एंबेसी ने भेजा, पीड़ित बोला- भारत जैसा कोई देश नहीं

भागलपुर। नौकरी के लिए सऊदी अरब गया भागलपुर का एक युवक 14 साल बाद घर लौटा है। जॉब के लिए सऊदी गया युवक एक हादसे के बाद दोषी करार दिया गया था। उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। जब परिजन को जानकारी हुई तो वे बेटे की वतन वापसी को परेशान हो गए। करीब 9 साल तक परिजन परेशान रहे। अगस्त 2024 में उनकी मुलाकात उदाकिशनगंज मधेपुरा के SDO से हुई। उन्होंने SDO को सारी कहानी बताई। फिर रऊड ने सऊदी अरब में इंडियन एंबेसी में जानकार को इस बारे जानकारी दी। इंडियन एंबेसी ने सारी जानकारी इकट्ठा की और फिर युवक को प्लेन और ट्रेन का टिकट कराकर भागलपुर भेजा। बुधवार को भागलपुर लौटे युवक का नाम मोहम्मद अमरुद्दीन है, जो 2014 में दोषी करार दिए जाने, 14 महीने तक जेल की सजा काटने और फिर 2015 में जमानत पर रिहा होने के बाद से 9 साल यानी 2024 तक सऊदी अरब में भटक रहा था। जिले के जगदीशपुर इलाके के सलेमपुर गांव के रहने वाले अमीरुद्दीन ने बताया कि जमानत पर रिहा होने के बाद उसके पास कोई काम नहीं था, पासपोर्ट और मोबाइल भी जब्त कर लिया गया था। इधर-उधर घूमकर किसी तरह 9 साल गुजारे। इस बीच परिवार वालों से कभी-कभी बात हो जाती थी। अमीरुद्दीन ने बताया कि सड़क दुर्घटना में मुझे दोषी करार देते हुए सजा दी गई, 14 महीने जेल में रहा। जब जमानत मिली तो मुझे 30 हजार रियाल (6,84,734 रुपए) जुमार्ना के तौर पर देना था। मैंने छोटे-मोटे काम कर इसे चुकाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया। धीरे-धीरे ये जुमार्ना बढ़कर 90 हजार रियाल यानी 20,54,203 रुपए हो गया। मेरा पासपोर्ट तभी मिल सकता था, जब मैं जुमार्ने की रकम चुका देता। लेकिन पैसे थे, मैं करीब 9 साल इधर-उधर भटकता रहा। इसी बीच मेरे किसी परिजन ने उदाकिशनगंज मधेपुरा के एसडीओ एम जेड हसन को मामले की जानकारी दी। फिर, एसडीओ ने सऊदी अरब में इंडियन एंबेसी में काम करने वाले अपने जानकार को मेरे बारे में बताया और मदद की अपील की। इसके बाद सऊदी अरब में इंडियन एंबेसी एक्टिव हुई और मुझसे कॉन्टैक्ट किया। फिर इंडियन एंबेसी ने ही मेरे जुमार्ने की राशि को माफ कराया और भागलपुर तक आने के लिए पहले प्लेन और फिर ट्रेन का टिकट कराया। अमीरुद्दीन ने बताया कि जिस एजेंसी ने मुझे सऊदी अरब में काम दिलाया था और मुझे वहां पहुंचाया था, उसने मेरा न तो वहां का लाइसेंस बनवाया था और न ही उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन था, जो मैं चला रहा था। इसी के चलते कोर्ट ने मुझे दोषी माना और मुझे जेल जाना पड़ा। अमीरुद्दीन ने कहा कि अब मैं अपने देश से कहीं नहीं जाऊंगा। अपने भारत जैसे कोई देश नहीं है, यहीं कुछ करके कमाऊंगा और परिवार के साथ रहूंगा। अमीरुद्दीन के पिता हाजी मोहम्मद कुतुबुद्दीन ने बताया कि 18 से 20 साल से मैं किडनी, शुगर जैसी बीमारी से परेशान था।

संक्षिप्त डायरी

कस्टमर बनकर आए चोर, दिनदहाड़े ज्वैलरी शॉप में चोरी

मोतिहारी। नगर थाना क्षेत्र में 1 अप्रैल को दिनदहाड़े एक ज्वेलरी शॉप से बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पानी टंकी के पास स्थित पूर्व सैनिक कमलेश गुप्ता की दुकान को दो शातिर चोरों ने अपना निशाना बनाया। गुरुवार को इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।कैसे दिया वारदात को अंजाम? 1 अप्रैल दे दिन दोनों चोर ग्राहक बनकर जेवरात दुकान में आए थे। दोनों दुकानदार की नजर बचाकर सोने-चांदी से भरी पोटली लेकर फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे उउळश कैमरे में कैद हो गई है, जिससे चोरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।पुलिस जांच में जुटीदुकानदार कमलेश गुप्ता ने नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि, अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। थाना प्रभारी विजय कुमार ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।शहर में बढ़ रही हैं चोरी की घटनाएं मोतिहारी में चोरी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पहले जहां चोरी की वारदातें रात में होती थीं, अब चोर दिनदहाड़े वारदात को अंजाम देने लगे हैं। पुलिस गश्त और निगरानी में कमी के कारण चोरों का मनोबल बढ़ता जा रहा है।

हाजीपुर में 5 लाख की छिनतई का खुलासा

हाजीपुर । मामला 29 मार्च 2025 का है, जब संस्कार कुमार और उनके स्टाफ रामबाबू महतो एक बैंक से 5 लाख कैश निकालकर घर जा रहे थे। इसी दौरान नगर थाना क्षेत्र के यादव चौक के पास दो अज्ञात बाइक सवारों ने रुपयों से भरा थैला छीन लिया। पीड़ितों ने इस घटना की सूचना फौरन पुलिस को दी।पुलिस ने घटना की जांच के लिए CCTV फुटेज खंगाले और एक आरोपी की पहचान करने में सफल रही। आरोपी सिंटू ग्वाला कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र के नयाटोला का रहने वाला है। वह कोढ़ा गैंग का सक्रिय सदस्य है। छापेमारी में 4 लाख बरामद, एक आरोपी फरार पुलिस ने स्थानीय अधिकारियों की मदद से आरोपी के घर पर छापेमारी की। इस दौरान लूटे गए 5 लाख में से 4 लाख बरामद कर लिया गया।सदर एसडीपीओ ओमप्रकाश ने बताया कि नगर थाना में कांड संख्या 353/25 के तहत धारा 394 (लूटपाट) में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की टीम दूसरे आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।

देव छठ मेला में 500 स्काउट गाइड की टीम तैनात

औरंगाबाद। देव छठ मेला में व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए स्काउट गाइड की टीम को तैनात किया गया है। औरंगाबाद, अरवल और रोहतास जिले से कुल 500 स्काउट गाइड मंगलवार से सेवा में जुट गए हैं। टीम, 4 अप्रैल तक मेला में तैनात रहेगी। जिला संगठन आयुक्त और राज्य सचिव श्रीनिवास कुमार ने बताया कि छठ पूजा में स्काउट गाइड की भूमिका महत्वपूर्ण है। स्काउट गाइड के छात्र भीड़ नियंत्रण में जुटे हैं। वे मेला क्षेत्र में एक तरफा रास्ता नियंत्रण, सूर्य कुंड और मंदिर परिसर में भीड़ नियंत्रण का कार्य कर रहे हैं। इनकी निगरानी के लिए स्काउट मास्टर और गाइड कैप्टन भी तैनात किए गए हैं। अरवल के जिला संगठन आयुक्त राजेश कुमार और रोहतास के जिला संगठन आयुक्त अरविंद कुमार सिंह समेत कई अधिकारी इस कार्य की देखरेख कर रहे हैं। सभी स्काउट गाइड को ड्रेस में रहने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले उन्हें विशेष ट्रेनिंग भी दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि स्काउट गाइड चार दिवसीय छठ मेला में व्रतियों की सेवा कर अपनी अलग पहचान बनाएंगे।

आर्मी में दो दोस्त,दोनों का एक-दूसरे की पत्नी से अफेयर

पूर्णिया। में स्कूल जा रही शादीशुदा शिक्षिका सोनी भारती (30) को बदमाशों ने गोली मार दी। सोनी अपने पति के दोस्त और प्रेमी बजरंग के साथ बुधवार की सुबह बाइक से स्कूल जा रही थी। तभी बदमाशों ने सोनी पर फायरिंग कर दी। गोली पीठ में लगी, घायल महिला टीचर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के वनभाग गांव की है। बजरंग आर्मी से रिटायर अधिकारी हैं। सोनी के पति चितरंजन भी आर्मी में ही है। वो कश्मीर में पोस्टेड हैं। पूर्णिया के न्यू सिपाही टोला निवासी सोनी भारती कटिहार जिले के कदबा थाना के उत्क्रमित मिडिल स्कूल कचड़ौ पश्चिम में शिक्षिका हैं। सोनी भारती ने अपने पति चितरंजन कुमार और प्रेमी बजरंग के साले ब्रजेश उर्फ छोटू पर शूटर हायर कर हमला कराने का आरोप लगाया है।सोनी भारती का कहना है कि, 2006 में चितरंजन से मेरी शादी हुई थी। हमारे 2 बच्चे भी हैं। चितरंजन और बजरंग दोनों आर्मी में थे। अच्छे दोस्त भी थे। 2002 में बजरंग ने वीआरएस लेकर आर्मी की नौकरी छोड़ दी। वो पूर्णिया आ गया। मेरे पति चितरंजन और बजरंग ने पूर्णिया के न्यू सिपाही टोला में जमीन खरीदी और आसपास ही घर बनवाया। सोनी भारती ने आगे बताया कि 'मेरे पिता की अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। इसी पर पति की नजर है। सविता (बजरंग की पत्नी) इस प्रॉपर्टी को हथियाने का दबाव मेरे पति चितरंजन पर बना रही थी। इसी प्रॉपर्टी के लिए पति मुझे धमकी देता रहता था।' 'पति चितरंजन ने प्रेमी बजरंग के साले के साथ मिलकर इससे पहले भी तीन बार हत्या की साजिश रची। लेकिन मां किसी तरह बच गई। इस बार पति के इशारे पर मुझे जान से मारने के लिए गुंडे भेजे गए थे। उन्हीं गुंडों ने फायरिंग की।' बेटी बोली- पापा को फंसाया जा रहा घटना को लेकर सोनी भारती की बेटी अनुष्का श्री का कहना है कि 'मेरे पिता चितरंजन कुमार जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हैं। पिता अधिकांश बाहर ही रहते थे, जिसके चलते मां सोनी भारती का पिता के दोस्त बजरंग कुमार से अफेयर शुरू हो गया।' सोनी भारती के प्रेमी बजरंग ने बताया कि 'मैं हर रोज की तरह बुधवार को भी सोनी को बिलौरी स्थित घर से उसके स्कूल छोड़ने जा रहा था।

हरियाणा में 1609 परिवारबी पी एल सूची से बाहर, इन लोगों पर होगी एफ आई आर आखिर क्यों हो रहा यह एक्शन?

हरियाणा सरकार ने नकली गरीबों पर सख्ती दिखाते हुए 1609 परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर कर दिया है। ये परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फर्जी तरीके से गरीब बने थे। सरकार ने 20 अप्रैल तक ऐसे परिवारों को खुद ही अपना नाम बीपीएल श्रेणी से कटवाने की चेतावनी दी है वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।चंडीगढ़। हरियाणा में नकली ह्यगरीबोंह्ण पर सरकार की सख्ती का असर दिखने लगा है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फर्जी तरीके से गरीब बने 1609 परिवारों को बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) की सूची से

बाहर कर दिया गया है। एक मार्च से एक अप्रैल तक अभियान चलाकर यह कार्रवाई की गई है।20 अप्रैल तक बीपीएल श्रेणी से नाम हटाने की चेतावनी फजीर्वाड़ा करके बीपीएल बने परिवारों को 20 अप्रैल तक खुद ही अपना नाम बीपीएल श्रेणी से कटवाने की चेतावनी दी गई है। इसके बाद सरकार ऐसे परिवारों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवा सकती है। यह मुद्दा हाल ही में हुए बजट सत्र के दौरान विधानसभा में उठा था।उस समय मुख्यमंत्री ने सदन में ही कार्रवाई के आदेश जारी किए थे। अब धरातल पर यह कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में अभी 51 लाख 96 हजार 380 परिवार बीपीएल श्रेणी में हैं। बीपीएल परिवार का लाभ उसी परिवार को मिलता है, जिनकी सालाना आय 1.80 लाख से कम हो। जांच के बाद होगी कार्रवाई सरकार को शक है कि इससे ज्यादा आय होने के बावजूद परिवारों ने कम आय भरते हुए

बीपीएल कार्ड बनवा लिया।

कई परिवारों की आमदनी इस स्लैब से अधिक है। इसके बावजूद उन्होंने परिवार का फर्जी बंटवारा कर लिया। कागजों में खुद को अलग-अलग दिखाकर बीपीएल परिवार वाले फायदे उठा रहे थे। ऐसे सभी लोगों के नाम काट दिए गए हैं। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के राज्य कोआर्डिनेटर सतीश खोला ने कहा कि फैमिली आईडी में गलत जानकारी देकर बीपीएल श्रेणी में आने वालों की छंटनी की जा रही है। ऐसे लोग खुद से जानकारी दुरुस्त नहीं करेंगे तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

सोनीपत में खौफनाक वारदात, उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार; पत्नी का दर्दनाक तरीके से कत्ल

सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत जिले में एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। एक युवक ने घरेलू कलह के चलते पत्नी की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी। यह घटना सोनीपत जिले के भैंसवान गांव की है। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस जांच में पता चला कि पति-पत्नी के आपसी विवाद में हंसता खेलता परिवार उजड़ गया है। पति-पत्नी में क्यों होता था झगड़ा? बताया गया कि घरेलू कलह के चलते साहिल का अपनी पत्नी पूजा से आए दिन झगड़ा होता रहता था। अभी इन दोनों की शादी को महज सवा साल ही हुआ था और एक दो महीने का बेटा भी है। डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित किया जानकारी के अनुसार, वह पत्नी पर शक करता था, जिसके चलते घरेलू कलह रहता था। उनकी सवा वर्ष पहले शादी हुई थी और दो माह का बेटा भी है। पत्नी को नागरिक अस्पताल से गांव खानपुर कलां स्थित भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। चाकू से वार करके दिया वारदात को अंजाम गांव भैंसवान खुर्द के साहिल की सवा साल पहले पूजा से शादी हुई थी। पूजा की छोटी बहन खुशी की भी साहिल के छोटे भाई से शादी हुई थी। साहिल पूजा पर शक करता था, जिसके चलते दोनों के बीच में कलह रहता था। बुधवार रात को दोनों खाना खाने के बाद कमरे में सोने के लिए चले गए। कमरे में जाने के बाद दोनों में बहस हो गई। इसके बाद साहिल ने घर से ही चाकू लेकर पूजा पर कई वार करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। लहूलुहान हालत में मिली पूजावहीं, शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो पूजा लहूलुहान मिली। परिजन उसे उठाकर नागरिक अस्पताल लेकर गए, जहां से उसे भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया।बरोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से बातचीत की। घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गन्नौर मार्केट कमेटी के सचिव पर गिरी गाज, सरकार ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

गन्नौर (सोनीपत)। सोनीपत में गन्नौर मार्केट कमेटी के सचिव दीपक सिहाग को सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर कृषि मंत्री के आदेश की अवहेलना और भ्रष्टाचार के गंभीर आर ोप लगे हैं। सिहाग के निलंबन के बाद उनके खिलाफ पहले से चल रही जांच भी तेज कर दी गई है।

श्री चंद प्रमोद जैन फर्म से जुड़ा है मामला मामला गन्नौर की अनाज मंडी में स्थित श्री चंद प्रमोद जैन फर्म से जुड़ा है, जिसे नई अनाज मंडी में

दुकान आवंटित नहीं हो पाई थी। फर्म मालिक गौरव जैन ने इस मामले में कृषि मंत्री को शिकायत कर उचित कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद मंत्री ने सिहाग को दुकान आवंटित करने का आदेश दिया।

दुकान आवंटन के बदले रिश्वत मांगी आरोप है कि सिहाग ने आदेश मानने से इनकार कर दिया और दुकान आवंटन के बदले रिश्वत मांगी। इस पर गौरव जैन ने मंत्री से फिर शिकायत कर दी। शिकायत के बाद कृषि मंत्री ने सिहाग के निलंबन का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के भी आदेश दिए।कृषि मंत्री के आदेश पर हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड ने सिहाग को पंचकूला स्थित मुख्यालय में अटैच कर दिया है, जहां वे बिना अनुमति नहीं जा सकते।

हरियाणा में गन्नौर मार्केट कमेटी

के सचिव दीपक सिहाग पर कृषि मंत्री के आदेश की अवहेलना और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ पहले से चल रही जांच भी तेज कर दी गई है। बताया गया कि मंत्री ने सिहाग को दुकान आवंटित करने का आदेश दिया। आगे विस्तार से पढिए पूरा मामला।

फरीदाबाद में लघु सचिवालय में बम की सूचना से मचा हड़कंप, सील किया पूरा भवन मौके पर भारी फोर्स तैनात

मौके पर भारी फोर्स तैनात

फरीदाबाद। फरीदाबाद में सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय में बम की सूचना मिलने के बाद हड़कंप मच गया। प्रशासन ने पूरे भवन को सील कर दिया है। बम निरोधक दस्ता बुलाए गए हैं। किसी को भी अंदर-बाहर नहीं जाने दिया जा रहा बताया गया कि फिलहाल बम निरोधक दस्ता लघु सचिवालय के अंदर जांच कर रहे हैं। जो लोग सचिवालय के अंदर हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है और जो बाहर हैं उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मौके पर भारी फोर्स तैनात वहीं, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। लघु सचिवालय के सभी प्रवेश द्वारों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बम है या नहीं यह जांच पूरी होने के बाद ही कहा जा सकता है। सचिवालय के बाहर लगी लोगों की भीड़ हालांकि, सचिवालय के बाहर जमा भीड़ से ऐसे लग रहा है कि जैसे यह पुलिस प्रशासन की तरफ से मॉक ड्रिल की जा रही हो। बताया गया कि लघु सचिवालय में विस्फोटक पदार्थ होने की सूचना किसी ने उपायुक्त के मेल पर भेजी थी।क्या थाना प्रभारी? थाना सेंट्रल प्रभारी सुनील कुमार का कहना है कि फिलहाल हमारा बम निरोधक दस्ता, खोजी कुत्ता दस्ता, क्राइम की टीम, साइबर स्टाफ जांच में जुटा हुआ है। अभी कुछ नहीं मिला है। जांच पूरी होने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है।

गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में कार चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक महिला की दर्दनाक मौत

कैथल। एक कार चालक ने गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से

घायल हो गया। कार चालक बाइक को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया था। मृतक की पहचान गांव बरोट निवासी 47 वर्षीय राखी देवी के रूप में हुई है जबकि गांव का ही दीपराज घायल हुआ है। गांव बरोट निवासी प्रवीन की शिकायत पर कार चालक के विरुद्ध सदर थाना में केस दर्ज किया गया है। शिकायत में बताया कि उसकी चाची राखी देवी दो अप्रैल को उनके पड़ोसी दीपराज के साथ बाइक पर गांव से कैथल सामान लेने के लिए आई थी। कैथल से वापस गांव आते समय वह भी उनके पीछे-पीछे अपनी बाइक पर जा रहा था। दोपहर करीब तीन बजे रेलवे फ्लाईओवर से थोड़ा पीछे सामने से आ रहे कार चालक ने ओवरटेक करते हुए दीपराज की बाइक को टक्कर मार दी। महिला की मौक पर ही मौत, कार चालक मौके से फरारटक्कर लगते ही दीपराज और उसकी चाची राखी देवी सड़क पर गिर गए। कार चालक बाइक को घसीटते हुए ले गया। कुछ दूरी पर जाकर कार रुक गई और चालक मौके से फरार हो गया। राहगीरों की सहायता से दोनों को नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया था। चंडीगढ़ जाते समय रास्ते में उसकी चाची राखी देवी की मौत हो गई। पुलिस ने दर्ज किया केस दीपराज को पंचकूला के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रवीन ने बताया कि उसके चाचा सुरेश कुमार की साल 2020 में मौत हो चुकी है। अब चाची अपने पीछे चार बच्चों को छोड़ गई है। इनमें से दो बच्चों की शादी हो चुकी है और दो अभी भी अविवाहित हैं। सदर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच एएसआइ जयपाल को सौंप दी है।

हरियाणा में बढ़ती गर्मी से लोग परेशान, भिवानी सबसे गर्म, 37 डिग्री के पार पहुंचा तापमान

हिसार। मौसम में परिवर्तन के साथ ही बुधवार को अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। प्रदेश के कई जिलों का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। भिवानी सबसे गर्म रहा और उसका अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही वीरवार से नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है। इससे तापमान पर असर आएगा। हवाएं चलने से तापमान में गिरावट भी हो सकती है। आज से पश्चिमी विक्षोभ होगा एक्टिव, इससे वातावरण में नमी बढ़ने की संभावना भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में आने वाले दिनों में तापमान खुश्क रहने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों ने बताया कि तीन अप्रैल से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा जिसका असर चार अप्रैल तक रहेगा। इस विक्षोभ से

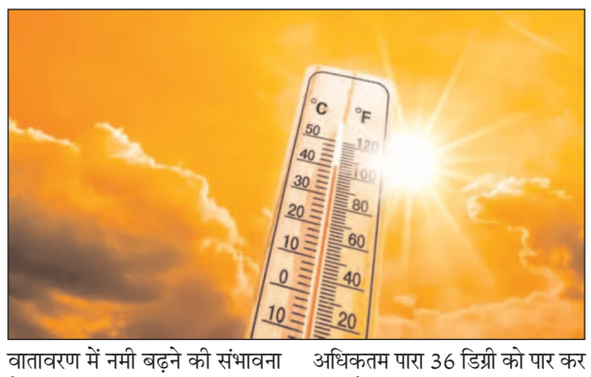

वातावरण में नमी बढ़ने की संभावना है।साथ ही बीच-बीच में आंशिक बादल छाने और हल्की से मध्यम गति की हवाएं भी चल सकती है। इससे तापमान पर असर आएगा। पिछले दिनों उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से मौसम में बदलाव हुआ था और अधिकतम तापमान नीचे गिरकर 29 डिग्री के आसपास पहुंच गया था।

कहां पर कितना दर्ज हुआ तापमान

मगर लगातार तापमान बढ़ने से अधिकतम पारा 36 डिग्री को पार कर गया है। इसमें हिसार, फरीदाबाद, नारनौल, सिरसा, रोहतक आदि शहर शामिल है।

अंबाला में न्यूनतम तापमान 15.5, अधिकतम तापमान 34.7, फरीदाबाद में न्यूनतम तापमान 15.3, अधिकतम तापमान 36.1, गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 13.9, अधिकतम तापमान 34.9 रहा। वहीं हिसार में न्यूनतम तापमान 12.9, अधिकतम तापमान 36.4, करनाल में न्यूनतम तापमान 10.9, अधिकतम तापमान 34.2, कुरुक्षेत्र में न्यूनतम तापमान 13.3, अधिकतम तापमान 33.9, नारनौल में न्यूनतम तापमान 12.3, अधिकतम तापमान 36.5, पानीपत में न्यूनतम तापमान 12.8, अधिकतम तापमान 34.1, रोहतक में न्यूनतम तापमान 15.5, अधिकतम तापमान 37, सिरसा में न्यूनतम तापमान 15, अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है।वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां धूप खिलने के कारण प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर दो से तीन डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अब मैदानी क्षेत्रों के साथ पहाड़ भी तपने लगे हैं। प्रदेश के छह स्थानों बरठीं, धौलाकुआं, मंडी, कांगड़ा, ऊना व सुंदरनगर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से पार चला गया है।

सूटकेस में मिला महिला का धड़, बाकी शरीर का अता-पता नहीं, फरीदाबाद में फैली सनसनी

हरियाणा के फरीदाबाद के मवई गांव के पास झाड़ियों में एक सूटकेस में एक महिला का धड़ मिला. यह जानकारी पुलिस ने बुधवार को दी. खेड़ी पुल थाना क्षेत्र में घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने अनुमान लगाया कि घटना करीब एक सप्ताह पहले हुई महिला के अन्य अंगों की तलाश जारी पुलिस ने शव को बी के अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है. इसने बताया कि महिला के अन्य अंगों की तलाश की जा रही है, जिसकी पहचान अभी नहीं हो पाई पुलिस ने कहा कि महिला की उम्र जो 35 से 40 साल के बीच प्रतीत होती है. ग्रामीणों ने कहा कि सड़क किनारे झाड़ी से दुर्गंध आने पर उन्होंने पुलिस से संपर्क किया. पुलिस उपायुक्त उषा देवी ने कहा, ह्यह्यसूटकेस में मिले धड़ की हालत बहुत खराब है. इस सूटकेस को यहां फेंके हुए करीब एक सप्ताह हो गया है.आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है.एक और महिला का सर सूटकेस में मिला इससे ही मिलता हुआ एक और केस कुछ दिन पहले आया था, जिसमें एक महिला का सर एक सूटकेस में मिला था. मामला मुंबई में विरार के मांडवी इलाके में पीरकुंडा दरगाह के पास का है जहां झाड़ियों में 13 मार्च को एक सूटकेस में एक महिला की कटी हुई मुंडी मिली थी. मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत मांडवी पुलिस स्टेशन ने इस मामले की जांच करते हुए महिला की पहचान का पता लगाया,

गुरुग्राम में लग्जरी बिल्डिंग और कोठियों पर गरजेगा बुलडोजर, डी एल एफें अवैध निर्माण पर बड़े एक्शन की तैयारी

नया गुरुग्राम। गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की इन्फोर्समेंट टीम की तरफ से डीएलएफ फेज-1 से पांच में अवैध निर्माण वाले मकानों पर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत की जा रही यह कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई साबित होने वाली है। उपायुक्त अजय कुमार ने डीटीपी इन्फोर्समेंट अमित मधोलिया के डिमोलीशन और सीलिंग प्लान को हरी झंडी दे दी है। इसके लिए डयूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर दिए हैं। चार अप्रैल से कार्रवाई शुरू की जाएगी। पांचों फेज में होने वाले इस कार्रवाई के लिए चार टीमें गठित की गई हैं। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में

पुलिस की तैनाती भी रहेगी।डीटीपीई कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, 31 मार्च तक पांचों फेज के 2100 से अधिक मकानों के विरुद्ध आक्यूपेशन सर्टिफिकेट रद करने, बिजली, पानी और सीवर कनेक्शन काटने के लिए डीटीपीई की तरफ से डीटीपी प्लानिंग को सिफारिश भेजी जा चुकी है। अब इन मकानों पर धरातल पर सीलिंग और तोड़फोड़ कार्रवाई भी चार अप्रैल से शुरू होने जा रही है। बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 13 फरवरी के आदेशों के मुताबिक, इन्फोर्समेंट टीम की तरफ से पांचों फेज में सर्वे कर 4500 से अधिक मकानों को चिह्नित किया गया था, जिनमें अवैध निर्माण, व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था।विभाग की तरफ से इन मकानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए। जिन मकानों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले उनके विरुद्ध रिस्टोरेशन के आदेश जारी करने शुरू कर दिए गए। इसके लिए इन्फोर्समेंट टीम के अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने पूरी तरह से कमर कस ली है। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहेगा।

पानीपत में स्कॉर्पियो कार ने बाइक सवार बी-फार्मा के 3 छात्रों को रौंदा, 2 की मौत, एक की हालत गंभीर

पानीपत। पानीपत में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां बाइक सवार तीन दोस्तों को स्कॉर्पियो कार ने टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में दो की मौत हो गई। वहीं, एक ही हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको इलाज के लिए पीजीआई रेफर किया गया है। नारा गांव के पास हुआ हादसा बता दें कि ये भीषण सड़क दुर्घटना पानीपत जिले के नारा गांव के पास पावर हाउस के नजदीक हुआ है। हादसे के शिकार हुए तीनों युव पीडीएम कॉलेज करसिन्धु के बी-फामेर्सी के द्वितीय वर्ष के छात्र थे।इस हादसे में मृतक की पहचान सौरभ निवासी राजीव कॉलोनी, सफीदों, और मृतक रवीश गोयत निवासी झांझकला, सफीदों के रूप में हुई है। वहीं, घायल चिराग जोशी निवासी दत्ता कॉलोनी गंभीर रूप से घायल है। पानीपत में एक दर्दनाक हादसे ने तीन दोस्तों के परिवारों को तबाह कर दिया। बाइक सवार तीनों दोस्तों को स्कॉर्पियो कार ने टक्कर मार दी जिसमें से दो की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है। यह हादसा नारा गांव के पास पावर हाउस के नजदीक हुआ। मृतकों की पहचान सौरभ और रवीश गोयत के रूप में हुई है।

पंजाब से चला ट्रक... बिहार थी मंजिल, हरियाणा पुलिस ने रोका

गैस कंटेनर में जो मिला उससे पुलिस भी सन्न

पंजाब के बठिंडा से बिहार जा रहा भारत पेट्रोलियम के गैस कंटेनर को टोहाना पुलिस ने चेकिंग के लिए रोक लिया। पुलिस ने चालक से दस्तावेज मांगे तो वह घबरा गया। पुलिस को शक हुआ तो गैस कंटेनर की जांच की गई। भारत पेट्रोलियम के गैस कंटेनर पंजाब के बठिंडा से चला था। इस ट्रक को हरियाणा होते हुए बिहार जाना था। लेकिन हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना में पुलिस ने ट्रक को रोक लिया। पुलिस ने ट्रक चालक से दस्तावेज मांगे, तो चालक घबरा गया। चालक ने जो दस्तावेज पुलिस को दिए वह गाड़ी के इंजन नंबर आरसी से मेल नहीं खा रहे है। गैस कंटेनर की तलाशी लेने पर पुलिस के होश भी फाख्ता हो गए। क्योंकि कंटेनर के अंदर से जो मिला वह हैरान करने वाला था। भारत पेट्रोलियम की गाड़ी से लाखों रुपये की शराब मिली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चालक के कब्जे से करीबन 40 लाख कीमत की 970 पेटी शराब बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपी शराब को पंजाब के बठिंडा से बिहार लेकर जा रहा था जिसे पुलिस ने काबू कर लिया। आरोपी चालक की पहचान राजस्थान के बाड़मेर निवासी तुलसाराम के रूप में हुई है। चालक को मिले थे 50 हजार रुपये आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसे इस शराब को

बिहार पहुंचाने पर पचास हजार रुपये मिलने थे। सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बलजीत सिंह ने बताया कि उनके पास गुप्त सूचना आई कि पंजाब राज्य से अवैध रूप से शराब अन्य राज्य में लेकर जा रही है। इसके बाद एएसआई राजेश कुमार व एचसी जयवीर सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने नाकाबंदी करते हुए पंजाब की तरफ से आ रहे उक्त भारत पेट्रोलियम के ट्रक को रुकवाया। इस दौरान पुलिस ने ट्रक चालक से पूछताछ की तो वह घबरा गया।कटर से कटवाया ट्रक का पिछला हिस्सा चालक ने बताया कि इसमें शराब रखी हुई है लेकिन ट्रक को पूरी तरह से बंद किया गया था। पुलिस ने कटर की मदद से ट्रक को कटवाया तो उसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। आरोपी द्वारा ट्रक में अलग-अलग केबिन बनाए गए थे जहां शराब को रखा गया था।

इंस्पेक्टर बलजीत सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एक्साइज एक्ट की धारा के तहत के केस दर्ज किया गया है लेकिन जो दस्तावेज उनके पास गाड़ी के मिले हैं वह भी सही नहीं पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी के कब्जे से 970 पेटी शराब की बरामद हुई है जिनके बैच नंबर भी मिटाए हुए थे।

दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय सऊदी अरब की जेलों में हैं बंद

- विदेश मंत्रालय ने कहा- 86 देशों में 10 हजार 152 भारतीय है कैद

नई दिल्ली (एजेंसी)। दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय सऊदी अरब की जेलों में बंद हैं। इस सूची में चीन समेत कई और देशों का नाम भी शामिल है। विदेश मंत्रालय की तरफ से संसदीय समिति को एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें भारत के बाहर जेलों में बंद भारतीयों की संख्या का ब्यौरा दिया गया है। ताजा मामला टेक महिंद्रा के अधिकारी अमित गुप्ता का है। उन्हें कतर में गिरफ्तार किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 86 देशों में 10 हजार 152 भारतीय जेलों में बंद हैं। ऐसे भारतीयों की सबसे ज्यादा संख्या सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में है। इन दोनों ही क्षेत्रों में भारतीय कैदियों की संख्या 2 हजार से ज्यादा है। इसके अलावा बहरीन, कुवैत और कतर में भी बड़ी संख्या में भारतीय जेल में बंद हैं। इनके अलावा नेपाल में 1317, मलेशिया में 338, चीन में 173 है कैदी बंद हैं। चीन, कुवैत, नेपाल, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात उन 12 देशों में शामिल हैं, जहां 100 से ज्यादा भारतीय कैद हैं। इनमें से 9 देश ऐसे हैं, जो ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन्स समझौते में शामिल है। इसके तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को उसके मुल्क में सजा काटने के लिए भेजने की अनुमति दी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते के बाद भी बीते तीन सालों में 8 कैदी भारतीय कैदियों को मुल्क वापस लाकर भारत की जेलों में रखा गया है। इनमें 3 ईरान, 3 ब्रिटेन, 2 कंबोडिया और 2 रूस से हैं। मंत्रालय का कहना है कि विदेश की जेलों से भारतीय नागरिकों की रिहाई या प्रत्यर्पण पर नियमित रूप से भारतीय मिशन काम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय मिशन और पोस्ट विदेश की जेलों में बंद नागरिकों को कानूनी समेत हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि संबंधित भारतीय दूतावास की तरफ से मदद हासिल भारतीय कैदियों से कोई भी फीस नहीं ली जाती है।

जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में बम की सूचना, कलेक्टर की सरकारी आईडी पर धमकी का ईमेल

जयपुर (एजेंसी)। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद खाली करावाया गया। कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की सरकारी आईडी पर धमकी का ईमेल आया था। गुरुवार सुबह 11:30 बजे मिले ईमेल की जानकारी कलेक्टर ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को दी। इसके बाद आनन-फानन में पूरे परिसर से लोगों को बाहर किया गया। करीब 200 कमरों की जांच के लिए बम स्क्वॉड और इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (ईआरटी) को बुलाया गया। हालांकि, करीब 2 घंटे के सर्च के दौरान किसी भी एजेंसी को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर खड़े कर्मचारियों ने बताया कि सुबह सामान्य दिनों की तरह कामकाज चल रहा था। अचानक 11:30 बजे के आसपास शोर मचने लगा। सभी को परिसर खाली करने के लिए बोला गया। जब तक कॉम्प्लेक्स के बाहर पहुंचे, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अंदर पहुंचने लगे थे। बाहर आकर जानकारी मिली कि कलेक्टर के पास बम की धमकी का ईमेल आया है। इसके बाद से सभी लोग डरे हुए हैं। दोपहर 2 बजे तक भी बिल्डिंग परिसर में बम स्क्वॉड की टीमें मौजूद थीं। अधिकारियों ने बताया कि जब तक एजेंसी क्लीयरेंस नहीं दे देती, अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। धमकी भरे ईमेल में लिखा गया कि जयपुर कलेक्टर ऑफिस एक भयंकर आईडी पाइप बम के टारगेट पर है। यह कदम 2-जी मामले में सवुक्कु शंकर के साथ हुए अनुचित व्यवहार और सादिक बलवा की हिरासत में हुई मौत का बदला लेने के लिए उठाया गया है। बम वीकेंड पर पहले से ही आज के लिए लगा दिया गया है। जो अन्ना यूनिवर्सिटी एमआईटी कैंपस के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तैयार हुआ है। हमारा लक्ष्य जन्नत देखना है। कलेक्ट्रेट हमारे साथ नष्ट हो जाएगा! आज का ऑपरेशन पूरा होने के बाद शहीद हो जाएंगे। बिलाल-रियाज जो यह पढ़ रहे हैं। आज का दिन है। आप जानते हैं कि क्या करना है। यह हमारा अंतिम कम्युनिकेशन होगा।

लॉरेंस गैंग के 5 गुर्गे गिरफ्तार, 7 पिस्तौल और 21 जिंदा कारतूस बरामद

-मुंबई पुलिस को शक इन गुर्गो के निशाना पर कोई सेलिब्रिटी था

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अंधेरी इलाके से लॉरेंस गैंग के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 7 पिस्तौल और 21 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस ने बुधवार को 2 अप्रैल को यह जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें शक है कि गैंग के निशाने पर कोई सेलिब्रिटी था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बताया कि विशेष सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने लॉरेंस गैंग के सदस्यों को शनिवार को हिरासत में लिया गया था। उनके हथियार ले जाने के पीछे के मकसद की जांच की जा रही है। गिरफ्तार लोगों की पहचान विकास ठाकुर उर्फ विक्की, सुमित कुमार दिलावर, श्रेयस यादव, देवेंद्र सक्सेना और विवेक गुप्ता के रूप में हुई है। ये सभी राजस्थान, बिहार और यूपी के रहने वाले हैं। सुमित कुमार और विकास हिस्ट्रीशीटर हैं। लॉरेंस गैंग सलमान खान को धमकियां दे रहा है। ऐसे में गैंग के पांच सदस्यों की गिरफ्तारी और उनके पास से हथियार बरामद होने के बाद इसे सलमान खान की सुरक्षा के लिए बड़े खतरे के रूप में भी देखा जा रहा है। पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है कि उनके निशान पर कौन था।

मजीठिया ड्रग तस्करी मामले में नया मोड़

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के नशा तस्करी से जुड़े मामले में नया मोड़ आ गया है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने मोहाली कोर्ट में याचिका दायर करके सर्च वारंट मांगे हैं। वहीं, जैसे ही यह मामला मजीठिया के वकीलों को पता चला तो उन्होंने भी कोर्ट में याचिका दायर कर एसआईटी द्वारा दर्ज अर्जी की कॉपी मांगी। मजीठिया के वकीलों ने साथ ही कोर्ट में पूछा है कि कौन सी जगह की तलाशी लेनी है, इस बारे में जानकारी दी जाए। हालांकि सरकार की तरफ से पेश हुए वकीलों ने इस एप्लिकेशन को गलत बताया है। वहीं, इस मामले में अब 5 अप्रैल को बहस होगी।

सोनिया गांधी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर कहा- देश को रसातल पर ले जा रही सरकार, बिल जबरन पारित किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी (सीपीपी) की बैठक में कहा कि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को केंद्र सरकार ने जबरन पारित करवाया है। यह विधेयक संविधान पर हमला है और हमारे समाज को स्थायी रूप से तोड़ने की बीजेपी की सोची-समझी रणनीति का एक हिस्सा है।

इस अवसर पर सोनिया गांधी ने उपस्थित कांग्रेस सांसदों से कहा, कि मोदी सरकार देश को रसातल में ले जाने का काम कर रही है। वह संविधान पर हमला कर उसे ध्वस्त करना चाहती है। इस तरह से तो संविधान महज कागजों में रह जाएगा। वन नेशन-वन इलेक्शन बिल भी संविधान का उल्लंघन है, जिसका हम विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सांसद मोदी सरकार की भारत को निगरानी राज्य में बदलने की मंशा को उजागर करने का काम करें।

बहुचर्चित वक्फ संशोधन बिल सोमवार देर रात लोकसभा में पारित हो गया, जिससे भारतीय राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को इस बिल पर

तीखा प्रहार करते हुए इसे समाज को बांटने वाला और संविधान को कमजोर करने वाला करार दिया। कांग्रेस संसदीय समिति को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए और कहा, भाजपा ने इस बिल को लोकसभा में बुलडोजर से पारित किया है। सोनिया गांधी ने लोकसभा में बहस के दौरान विपक्षी सांसदों को अपनी बात रखने का मौका न मिलने की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, यह बेहद चिंताजनक है कि विपक्षी सांसदों को अपनी बात कहने नहीं दी जाती। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भी अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने सत्ता पक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप भी लगाया। सोनिया गांधी ने भाजपा के प्रस्तावित एक देश, एक चुनाव कानून का भी विरोध किया। उन्होंने इसे संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ बताते हुए कहा कि कांग्रेस इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी और इसे निरस्त करने की मांग करेगी।

नए संसद भवन पर टिप्पणी

सोनिया गांधी ने नए संसद भवन को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, अतीत में हम सहकर्मियों से मिल सकते थे, अन्य दलों के नेताओं से बातचीत कर सकते थे और मीडिया के साथ जुड़ सकते थे। लेकिन अब यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रक्षा और विदेश मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा चाहती थी, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने चीन द्वारा भारत की सीमाओं पर पेश की जा रही चुनौतियों और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 19 जून 2020 को दिए गए बयान की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, चीन से आयात में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे हमारे एमएसएमई उद्योग नष्ट हो रहे हैं। यह अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है।

यहां बताते चलें कि लोकसभा में बुधवार रात को वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। रात 2 बजे की गई वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया, जिसमें 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाले।

ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान - बीजेपी सरकार हटी तो वक्फ संशोधन विधेयक होगा रद्द

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा में पारित वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की सरकार केंद्र से हटेगी, तो इस वक्फ बिल को रद्द कर दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर देश को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करता है।

उन्होंने कहा, जब केंद्र में नई सरकार बनेगी, तब इस कानून में संशोधन किया जाएगा और इसे रद्द कर दिया जाएगा। यहां बताते चलें कि लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने इस बिल के खिलाफ मतदान किया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने इस विधेयक को राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि संविधान संसद को इस संबंध में कानून पारित करने का अधिकार नहीं देता। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्ति मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का हिस्सा है। इसलिए राज्यों को इस पर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। गौरतलब है कि लोकसभा में बिल पास होने के बाद सरकार ने इसे राज्यसभा में पेश किया है। विपक्ष ने इस विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। इस मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है और आने वाले दिनों में इसे लेकर राजनीतिक दलों के बीच टकराव और बढ़ सकता है।

महिला समृद्धि योजना पर रेखा गुप्ता, जल्दबाजी में आप सरकार की तरह गलती नहीं करना चाहती

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में गरीब महिलाओं को 2500 रुपए मासिक आर्थिक सहायता का वादा करके सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को आम आदमी पार्टी (आप) लगातार घेर रही है। नेता विपक्ष आतिशी की ओर से बार-बार रेखा सरकार से पूछा जा रहा है कि महिलाओं के खाते में पैसे कब आएंगे? इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक इंटरव्यू में विस्तार से योजना पर बात कर बताया कि क्यों इसमें वक्त लग रहा है। मुख्यमंत्री रेखा ने कहा कि वह जल्दबादी में आप सरकार की तरह गलती नहीं करना चाहती हैं।

महिला समृद्धि योजना से जुड़े सवाल पर रेखा गुप्ता ने कहा, जब कोई सरकार बनती है, तब बजट आवंटन आवश्यक है, योजना की रूपरेखा, नियम बनाने पड़ते हैं। रजिस्ट्रेशन पूरा करना होता है और उसकी जांच होती है। यह एक ही बार पैसा देने की योजना नहीं है। हमें एक टिकाऊ रूपरेखा बनानी ताकि केवल योग्य लाभार्थियों को इसका लाभ मिले। आप सरकार ने योजनाओं की घोषणा कागजों पर की लेकिन एक साल से ज्यादा चला नहीं सकी। हम केजरीवाल सरकार वाली गलती नहीं करना चाहते हैं। रेखा ने कहा कि हमारी सरकार ने गरीब महिलाओं के लिए मदद का वादा किया। हमें सावधानीपूर्वक योग्यता की शर्तें तय करनी हैं ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके, जैसा कि ईडब्ल्यूएस स्कीमों में होता कि फायदा अक्सर अयोग्य लोगों को मिल जाता है। किर्यान्वयन में समय लगता है, लेकिन हम अपने हर वादे को पूरा करने वाले है। सीएम ने कहा, हमें नियम और शर्तें बनानी हैं। हमें ऐसी रूपरेखा बनानी है कि सही लोगों को ही फायदा मिले।

गुप्ता ने आप पर पलटवार कर कहा कि उन्होंने पंजाब में इसी तरह का वादा किया लेकिन तीन साल बात भी लागू नहीं कर सके है। आलोचना करना उनका राजनीतिक खेल है और इसमें कोई वजन नहीं। उन्हें अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में 10 साल पहले मुफ्त वाई-फाई देने का वादा किया था। मुझे बताइए दिल्ली के किस हिस्से में मुफ्त वाई-फाई है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए कोई विशेष तारीख देने से इंकार करते हुए कहा कि विधानसभा सत्र अभी समाप्त हुआ है और सरकार को अभी एक महीना ही हुआ है। उन्होंने कहा कि एक महीने पुरानी सरकार से योजनाओं को इतनी जल्दी लागू करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सीएम ने कहा, नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है। हमारी सरकार ने बस अभी बजट पेश किया है। यह एक बहुत बड़ा काम था। हमें ओपनिंग बैलेंस का आकलन करना है और यह देखना है कि वित्तीय स्थिरता के साथ कितने लाभार्थियों को मदद दे सकते हैं। हम इस योजना को फंड देने के लिए वेतन देना नहीं रोक सकते हैं। हमें दोनों प्राथमिकताओं में बैलेंस रखना होगा। पिछली सरकार ने अस्पतालों के प्रॉजेक्ट अधूरे छोड़ दिए। स्कूल और कॉलेज बनाने में विफल रही और दिल्ली के 12 सरकारी कॉलेज में वेतन नहीं दे सकी। सीएम ने कहा, हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि वेतन दिए जाएं, इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास हो और सभी सेक्टर में शासन प्रभावशाली हो।

तेलंगाना में 400 एकड़ में फैले कांचा गचीबावली जंगल को काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, प्रोटेस्ट पर उतरे हैं छात्र

नई दिल्ली (एजेंसी)। सर्वोच्च न्यायालय ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास कांचा गाचीबोवली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का स्वतः संज्ञान लिया और तेलंगाना के मुख्य सचिव को सरकार की कार्रवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह बनाया। गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, न्यायालय ने मौजूदा पेड़ों की सुरक्षा को छोड़कर, क्षेत्र में सभी गतिविधियों को रोक दिया और चेतावनी दी कि अनुपालन न करने पर सख्त परिणाम भुगतने होंगे।

तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में व्यापक वनों की कटाई दिखाई गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्षों की समीक्षा करने के बाद, पेड़ों को हटाने के पीछे की जल्दबाजी पर सवाल उठाया और राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या उचित पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की गई थी। अदालत ने विशेष रूप से इस बात पर जवाब मांगा कि क्या पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) प्रमाण पत्र जारी किया गया था और क्या इतने बड़े पैमाने पर विनाश करने से पहले वन अधिकारियों से अपेक्षित अनुमति ली गई थी।

अदालत ने पूछा इन गतिविधियों को शुरू करने की क्या मजबूरी थी? इस बात पर जोर देते हुए कि क्षेत्र में मोर और अन्य वन्यजीवों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि यह एक वनाच्छादित आवास है। अदालत में पेश किए गए फोटोग्राफिक साक्ष्यों से पता चला कि लगभग 100 एकड़ में भारी मशीनरी तैनात करके जमीन के बड़े हिस्से को साफ कर दिया गया। अदालत का निर्देश स्पष्ट था- अगले आदेश तक, क्षेत्र में सभी गतिविधियाँ बंद होनी चाहिए, और इसका पालन न करने पर मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

24 घंटे में दूसरी बार पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन, एलओसी पर 20 मिनट तक चली गोलियां

नई दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जो तीन दिनों में इस तरह की दूसरी घटना है। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा बिना उकसावे के की गई गोलीबारी का भारतीय सेना ने कड़ा जवाब दिया। यह तीन दिनों में पाकिस्तान द्वारा किया गया दूसरा संघर्ष विराम उल्लंघन है। मंगलवार को, पाकिस्तान ने पुंछ में नियंत्रण रेखा पर बारूदी सुरंग विस्फोट के बाद एक और संघर्ष विराम उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना ने कथित तौर पर उन्हें कवर फायर प्रदान करते हुए सीमा पार घुसपैठियों को धकेलने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने तेजी से जवाब दिया, जिससे खतरा खत्म हो गया। सूत्रों से पता चला है कि गोलीबारी का उद्देश्य भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों को घुसाना था। खुफिया जानकारी से पता चला है कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए एलओसी के पार आतंकवादी बॉर्डर एक्शन टीम (BAT) भेजने की कोशिश कर रहा था। हालांकि, भारतीय सैनिकों की सतर्कता ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, भारत की जवाबी कार्रवाई में चार से पांच पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए। 1 अप्रैल को संघर्ष विराम उल्लंघन के बाद, घायल पाकिस्तानी सैनिकों की तस्वीरें सामने आईं, जो भारत की प्रतिक्रिया के प्रभाव की पुष्टि करती हैं। इसके अलावा, पाकिस्तानी सेना के जवानों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो इस बात का संकेत देती हैं कि उनकी तरफ़ से भी हताहत हुए हैं। एक पाकिस्तानी समाचार पोर्टल ने भारत के जवाबी हमले में मारे गए कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए सैनिकों की फुटेज प्रसारित की, जो इस रिपोर्ट की पुष्टि करती है कि 1 अप्रैल के हमले में कई पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए थे।

अजित पवार के पावर पर लगाम, अब शिंदे की नजर से गुजरेगी हर एक फाइल

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आने और भाजपा की सरकार बनने के बाद भी यहां सियासी नाराजगी दूर नहीं हो पाई है। लेकिन अब राजनैतिक खींचातानी कम होती दिखाई दे रही है। पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गई तो वह होम मिनिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन वह भी नहीं मिला तो कुछ मंत्रालय लेकर डिप्टी सीएम बन गए। इसके बाद भी उनकी नाराजगी बनी ही रही। कभी प्रभारी मंत्रियों को लेकर तो कभी मंत्रालयों के फैसलों को लेकर वह खफा दिखते थे। एक मलाल यह भी रहा कि अजित पवार को उनसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस सरकार में उनका कद बढ़ा दिया गया है। अब महाराष्ट्र सरकार के कामकाज की कोई भी फाइल उनसे होकर ही सीएम देवेंद्र फडणवीस तक जाएगी। नई सरकार के गठन के बाद से अजित पवार के पास फाइल जाती थी क्योंकि वह वित्त मंत्री थे और फिर सीएम फडणवीस उसे देखते थे।

महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी सुजाता सौनिक की ओर से आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी फाइल पहले वित्त मंत्री (डिप्टी सीएम अजित पवार) के पास जाएगी और फिर उन्हें शहरी विकास और हाउसिंग मिनिस्टर (डिप्टी सीएम

एकनाथ शिंदे) के पास भेजा जाएगा। अंत में सभी फाइलें सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास जाएंगी। इस तरह एकनाथ शिंदे के कद का पूरा ख्याल रखा गया है और वह एक तरह से अजित पवार से सीनियर होंगे। शिवसेना के नेताओं की लगातार यह शिकायत थी कि उनके लीडर एकनाथ शिंदे को सरकारी कामकाज उतना महत्व नहीं मिल रहा है, जितना उनका कद है और पार्टी की ताकत है। ऐसे में अब शिवसैनिकों के गुस्से को भी कंट्रोल किया जा सकेगा। स्थानीय निकाय के चुनावों से पहले यह फैसला अहम है। अब नई व्यवस्था आ गई है, जिसके तहत पहले फाइल अजित पवार पर ही जाएगी। फिर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पास फाइलें आएंगी और उनके पास करने के बाद ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंचेंगी। इससे पहले जब एकनाथ शिंदे ही सीएम थे तो यह व्यवस्था थी कि पहले अजित पवार के पास फाइल पहुंचती थी और फिर देवेंद्र फडणवीस के पास से होते हुए मुख्यमंत्री तक पहुंचती थी। अब एक बार फिर से वैसी ही व्यवस्था है, बस क्रम बदल गया। अब फडणवीस सीएम हैं और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन अजित पवार से शिवसेना लीडर का कद बड़ा कर दिया गया है।

वक्फ बिल के पास होने पर योगी की दो टूक चेतावनी, अब प्रदेश में माफियागीरी नहीं चलेगी

प्रयागराज (एजेंसी)। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रृंगवेरपुर धाम पहुंचे और उन्होंने प्रभु श्रीराम और निषादराज की मित्रता का स्मरण दिलाया। इस दौरान महाकुंभ की सफलता और प्रयागराज को मिली वैश्विक पहचान के लिए प्रयागराजवासियों को श्रेय दिया।

इस दौरान विरोधियों पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि पिछली सरकारें नहीं चाहती थीं कि पौराणिक शहर को पहचान मिले। उनके लिए अपना वोट बैंक है, निषादराज की पौराणिक भूमि पर भी कब्जे की साजिश। जब हम महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, तब कुंभ की भूमि को भी वक्फ की भूमि बता दिया? भू माफिया प्रदेश में नहीं रह सकते। अब प्रदेश में माफियागीरी नहीं चलेगी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए योगी ने कहा कि हम पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के प्रति आभारी हैं। वक्फ संशोधन विधेयक

लोकसभा में पारित हो गया, आज राज्यसभा में पारित होगा। इस मौके पर योगी ने 579 करोड़ की 181 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसके साथ ही वह विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक तथा प्रशस्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि आज यहां पर निषादराज परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए 580 करोड़ की योजना की सौगात देने आया हूं। प्रयागराज का मतलब महामिलन स्थल। गंगा-यमुना और सरस्वती का संगम। यहां निषादराज और भगवान राम के मिलन का भी संगम भी हुआ।

महाकुंभ ने बहुत कुछ दे दिया

सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ ने बहुत कुछ दे दिया प्रदेश, देश और सनातन धर्मावलिबंयों को। इतना बड़ा आयोजन रामभक्त ही कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रनिष्ठा चाहिए। जिनके मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं, वह इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकता।

एमएसपी पर राज्य सरकारों की सिफारिशों को क्यों दरकिनार कर रहा केंद्र

नई दिल्ली (एजेंसी)। अलग-अलग सूबों में फसल उत्पादन की अलग लागत आने के बावजूद केंद्र देश भर के लिए एक ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय करती है। हालांकि, कोई भी राज्य एमएसपी के ऊपर जरूरत के हिसाब से बोनस दे सकता है, लेकिन केंद्र इस तरह की किसी भी कोशिश को ठीक नहीं मानती। बहरहाल, मुद्दा यह है कि केंद्र सरकार एमएसपी एक ही तय करती है लेकिन क्या राज्य सरकारें इसके लिए अपनी ओर से कोई प्रस्ताव भेजती हैं? हां बिल्कुल ऐसा ही है। अब सवाल यह आता है किस किस राज्य ने धान, गेहूं जैसी प्रमुख फसलों के लिए केंद्र को कितनी एमएसपी का प्रस्ताव दिया है।

केंद्र ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए धान की एमएसपी 2300 रुपये क्विंटल तय की थी। जबकि उस साल के लिए महाराष्ट्र ने धान की एमएसपी 4661 रुपये प्रति क्विंटल मांगी थी। केरल ने 3690 रुपये और कर्नाटक सरकार ने 3426 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी की मांग की थी। उत्तर प्रदेश ने 3000 और बिहार सरकार ने 3201 रुपये की मांग की थी। तेलंगाना ने 5428 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी मांगी थी। राज्य सरकारों ने केंद्र से अपने सूबे के लिए चाहे जितनी भी एमएसपी का प्रस्ताव दिया हो, लेकिन केंद्र ने प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया। केंद्र ने देश में धान की संपूर्ण लागत महज 2008 रुपये प्रति क्विंटल मानी। ताज्जुब यह है कि सी-2 कॉस्ट बताने के बावजूद केंद्र सरकार ने इस बात को माना नहीं। केंद्र सरकार ने ए2+एफएल फार्मूले के आधार पर धान की उत्पादन लागत को प्रति क्विंटल 1533 रुपये बताया और उस पर न्यूनतम 50 फीसदी मुनाफा जोड़कर 2300 रुपये एमएसपी तय कर दी।

वहीं गुजरात सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर एक अप्रैल 2025 से शुरू हुए रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए गेहूं की एमएसपी 4050 रुपये प्रति क्विंटल तय करने की मांग उठाई थी। पश्चिम बंगाल ने 3350 और महाराष्ट्र ने गेहूं की एमएसपी भी 4461 रुपये मांगी। जबकि केंद्र ने एमएसपी 2425 रुपये तय की है। यानी इन सूबों की मांग के मुकाबले एमएसपी बहुत कम है। राज्यों से आए प्रस्तावों को दरकिनार कर केंद्र ने एक औसत निकलकर यह बताया कि गेहूं की संपूर्ण लागत 1720 रुपये प्रति क्विंटल आई है। हालांकि सरकार ने सी-2 कॉस्ट के आधार पर एमएसपी तय नहीं किया। केंद्र सरकार ने गेहूं की ए2+एफएल फार्मूले के आधार पर उत्पादन लागत 1182 रुपये ही मानी। इस पर 105 फीसदी का मुनाफा देकर पूरे देश के लिए 2425 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी तय कर दी।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अनुसार रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के दौरान गेहूं की एमएसपी के लिए आठ

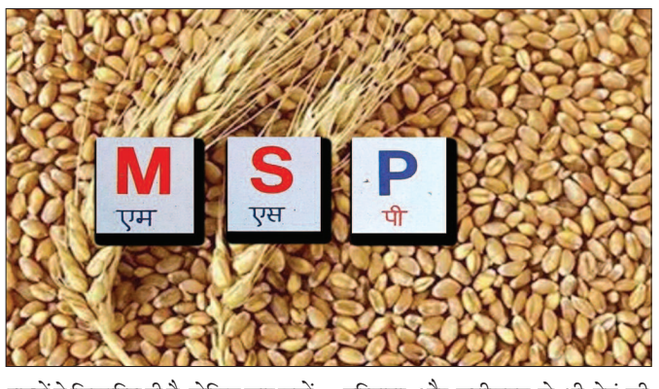

राज्यों ने सिफारिश दी है, लेकिन चार सूबों ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया। इसमें गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ से भी गेहूं की एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव या सुझाव नहीं दिया है।

क्या किसी नए किरदार की तैयारी कर रही हैं राशि खन्ना

राशि खन्ना इन दिनों अपने सोशल मीडिया पोस्ट से फैंस की जिज्ञासा बढ़ा रही हैं। हाल ही में उन्होंने सेट से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह मज़ेदार अंदाज़ में खाना बनाते हुए पंजाबी सीखती नजर आईं। अभिनेत्री ने हाल ही में एक स्वादिष्ट और सेहतमंद दाल चिल्ला बनाते हुए अपना एक वीडियो साझा किया, लेकिन सिर्फ़ खाना पकाने की वजह से ही सभी का ध्यान नहीं गया—बल्कि पंजाबी बोलने की उनकी सहज आदत ने भी सबका ध्यान खींचा!

जिस चीज़ ने उनके फ़ॉलोअर्स को सबसे ज़्यादा आकर्षित किया, वह थी उनकी मज़ेदार पंजाबी कमेंट्री-सत श्री अकाल! आज मेरे शॉट नू टाइम लाग रेहा ऐ, ते मैं आज दाल चिल्ला बना लवा। ऐ हैगा ऐ साडा स्वीट सा किचन ऑन सेट! तुआनू मैं रेसिपी दसदा, तुसी भी ट्राई करो! इस पोस्ट के बाद फैंस में उत्सुकता बढ़ गई और कई लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि क्या राशि खन्ना किसी पंजाबी प्रोजेक्ट में नज़र आने वाली हैं?

आखिरकार, वह तेलुगु, तमिल, हिंदी फिल्मों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखा चुकी हैं, तो अब पंजाबी इंडस्ट्री में कदम रखना कोई हैरानी की बात नहीं होगी। इन्हीं अटकलों को और हवा देते हुए, राशि को हाल ही में एक्सेल एंटरटेनमेंट के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया, जिससे उनके किसी नए और रोमांचक प्रोजेक्ट का अंदाजा लगाया जा रहा है। 'द साबरमती रिपोर्ट' की सफलता और उसमें एक पत्रकार की उनकी दमदार भूमिका के बाद, फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वह अगला कौन-सा चैलेंज लेने वाली हैं। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर तय है कि राशि खन्ना अपनी एनर्जी, डेडिकेशन और नए अनुभवों के लिए जुनून के साथ हमेशा फैंस को चौंकाती रहती हैं। फिर चाहे कोई नई भाषा सीखना हो या सेट पर कुछ खास पकाना, वह कभी भी अपने प्रशंसकों को सरप्राइज देने से पीछे नहीं हटतीं!

जाट में सनी देओल संग नजर आएंगी उर्वशी रौतेला

अभिनेत्री उर्वशी रौतेला 12 साल बाद अभिनेता सनी देओल संग काम कर रही हैं। रौतेला जल्द ही 'जाट' के गाने 'टच किया' में नजर आएंगी। अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर अभिनेत्री काफी उत्साहित हैं। उर्वशी ने कहा, 12 साल बाद सनी देओल सर के साथ काम करना शानदार है और इसके लिए मैं खुद को लकी मानती हूं। वह बेहतरीन एक्शन हीरो हैं और मैं 'जाट' में उनके साथ काम करने के लिए रोमांचित हूं। उर्वशी रौतेला साल 2013 में आई फिल्म 'सिंह साहब द ग्रेट' में सनी देओल के साथ काम कर चुकी हैं। उन्होंने कहा, जब मैं 19 साल की थी, तब उन्होंने मुझे 2013 की हिट फिल्म 'सिंह साहब द ग्रेट' में काम दिया था, जो मेरी पहली मुख्य भूमिका वाली फिल्म थी। हम अपकमिंग फिल्म के लिए फिर से साथ हैं। उर्वशी ने कहा, 'सिंह साहब' तो बस शुरुआत थी। 'जाट' एक अलग लेवल पर होगी। 1 अप्रैल को दर्शकों के सामने कुछ खास आने वाला है! उनके साथ 12 साल बाद पर्दे पर वापसी को लेकर मैं उत्साहित हूं। मैत्री मूवी मेकर्स ने रविवार को गाने का स्टिल पोस्टर जारी किया, जिसमें उर्वशी की एक झलक भर दिखी। निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा, बड़े पैमाने पर जाट के ट्रेलर को लॉन्च करने के बाद अब फिल्म से एक धमाकेदार गाने का समय आ गया है। 'जाट' का पहला गाना 'टच किया' 1 अप्रैल को जारी होगा। उर्वशी रौतेला की फिल्म 'सिंह साहब द ग्रेट' सिंह साहब (सनी देओल) की कहानी है, जो जिम्मेदार के साथ ही ईमानदार इंसान है और रिश्तों को निभाने में विश्वास रखता है, लेकिन भूदेव (फिल्म में खलनायक) एक चालाक आदमी है और वह उसके खिलाफ साजिश रचता है। ऐसे में सनी देओल भूदेव को सबक सिखाने के लिए आगे आता है।

वर्कफ्रंट की बात करें तो उर्वशी रौतेला हाल ही में बॉबी कोली के निर्देशन में बनी फिल्म 'डाकू महाराज' में नजर आई थीं। फिल्म में उर्वशी रौतेला के साथ अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण, श्रद्धा श्रीनाथ, बॉबी देओल, प्रज्ञा जायसवाल, सचिन खेडेकर, मकरंद देशपांडे, आदुकलम नरेन, नितिन मेहता, रवि किशन, वीटीवी गणेश, ऋषि और चांदनी चौधरी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। वहीं, 'जाट' का निर्देशन गोपीचंद मलिनेनी ने किया है। सनी देओल के साथ रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह, सैयामी खेर और रेजिना कैसंड्रा भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री ने मिलकर किया है, जो 10 अप्रैल को हिंदी के साथ तमिल और तेलुगू में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ईशा देओल ने जताई इस फिल्म के री-रिलीज की इच्छा

हाल ही में तुमको मेरी कसम फिल्म रिलीज से ईशा देओल ने बड़े पर्दे पर वापसी की। अभिनेत्री से फिल्मों के री रिलीज को लेकर सवाल किया गया। इसके जवाब में अभिनेत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह धूम को री-रिलीज के लिए चुनेंगी। उन्होंने बताया कि धूम एक शानदार फिल्म थी, जिसने सबके जहन में एक अलग जगह बनाई थी।

बात करें धूम की तो इसमें ईशा देओल के अलावा जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा ने शानदार भूमिका निभाई थी। इसके अलावा ईशा ने कहा कि ना तुम जानो ना हम भी दोबारा वापस आए, जो एक बहुत प्यारी प्रेम कहानी पर आधारित थी। अगर ईशा देओल के काम की बात करें तो वह इस समय 'तुमको मेरी कसम' में नजर आईं, जिसमें उन्होंने वकील का किरदार निभाया है। फिल्म का निर्देशन विक्रम भट्ट ने किया था। इससे पहले ईशा देओल 2015 में आई फिल्म 'किल देम यंग' में नजर आईं थीं।

इंडस्ट्री जिंदा है, आगे भी बढ़ेगी

बॉलीवुड में इन दिनों कंटेंट और एक्सपेरिमेंट्स को लेकर काफी बहस हो रही है। हाल ही में रिलीज हुई डिप्लोमैट के बाद एक्टर जॉन अब्राहम ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की। उनका कहना है कि अच्छी फिल्में बन रही हैं, लेकिन इंडस्ट्री को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए और सपोर्ट और आजादी की जरूरत है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बॉलीवुड के मौजूदा हालात और सोशल मीडिया पर बढ़ती नेगेटिविटी को लेकर अपनी राय रखी।

हम अच्छी फिल्में बना रहे हैं, लेकिन हमें आजादी भी चाहिए

बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में जॉन ने कहा, फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो प्यार और अपनापन है, वही मुझे डराता भी है। मुझे बॉलीवुड की चिंता होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ मैं ही कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हां, कुछ लोग हैं जो बदलाव लाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं एक कमर्शियल हीरो हूं। आप मुझे एक बड़े सेटअप में डालिए, मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन जब हम कुछ नया करना चाहते हैं, तो हमें उसकी आजादी भी मिलनी चाहिए। हमें अपने आइडियाज को पूरा करने के लिए सपोर्ट और फंडिंग की जरूरत होती है। हर दिन कोई न कोई बॉलीवुड के खत्म होने की भविष्यवाणी करता है, लेकिन सच तो यह है कि हम लगातार अच्छी फिल्में बना रहे हैं और इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। फिल्म डिप्लोमैट की बात करें तो यह एक पॉलिटिकल थ्रिलर है, जिसमें जॉन अब्राहम ने एक इंटेंस किरदार निभाया है। बिना ज्यादा प्रमोशन के भी इस फिल्म ने दर्शकों का ध्यान खींचा और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। जॉन की परफॉर्मेंस को भी सराहा गया।

जॉन अब्राहम की आने वाली फिल्म

जॉन अब्राहम जल्द ही तेहरान में नजर आएंगे। यह एक इंटेंस जियोपॉलिटिकल थ्रिलर होगी, जिसमें उनके साथ मानुषी छिल्लर भी होंगी। इस फिल्म को दिनेश विजान प्रोड्यूस कर रहे हैं।

क्या वाकई दिशा वकानी की जगह काजल पिसल निभाएंगी दया बेन की भूमिका?

टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा लंबे वक्त से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। इस शो का हर किरदार बेहद खास है और दर्शकों से सीधे तौर पर जुड़ा है। मगर, जेठालाल और दयाबेन की बात ही अलग है। दयाबेन का किरदार अभिनेत्री दिशा वकानी ने बड़ी ही खूबसूरती से अदा किया। साल 2017 में वे मैटरनिटी लीव पर चल गईं। तब से फैंस शो में उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, अब दिशा वापस नहीं आएंगी। शो के निर्माता असित मोदी भी इसकी पुष्टि कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि मेकर्स को दिशा का रिप्लेसमेंट भी मिल गया है।

कयासों को बताया फेक न्यूज

कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि अभिनेत्री काजल पिसल अब तारक मेहता शो में दयाबेन की भूमिका करती दिखेंगी। इस तरह के कयासों पर खुद काजल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे दावों को फेक न्यूज बताया है। काजल ने स्पष्ट किया है कि वे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन की भूमिका नहीं अदा कर रही हैं। हालांकि, काजल ने यह भी कहा कि उन्होंने शो के लिए ऑडिशन दिया था। मैं झनक में काम कर रही हूं दावे किए जा रहे हैं कि काजल पिसल ने अब दिशा वकानी को रिप्लेस कर दिया है। उनकी तस्वीर भी वायरल हो रही है। इस बारे में जूम से बातचीत में काजल पिसल ने स्पष्ट किया कि ऐसी खबरें पूरी तरह झूठ हैं। साथ ही बताया कि तस्वीर पुरानी है। काजल ने कहा कि उनके पास इस खबर को लेकर कई कॉल और मैसेज आ रहे हैं, लेकिन इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। काजल ने कहा, मैं पहले से ही झनक में काम कर रही हूं। ऐसे में यह खबर झूठ है। हां, मैंने दया बेन के लिए साल 2022 में ऑडिशन दिया था और वो फोटो अब वायरल हो रही है। अब मैं सिर्फ यही कहूंगी कि शो में मेरे काम करने की खबर फेक न्यूज है।

परिवार के साथ समय बिता रहीं दिशा

बता दें कि दिशा वकानी ने नवंबर 2015 में शादी रचाई। साल 2017 में वे मैटरनिटी लीव पर चली गईं। बीच-बीच में उनकी वापसी की खबरें आती रहीं, लेकिन दिशा ने शो में वापसी नहीं की। साल 2022 में उन्होंने अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया। अभिनेत्री ने कथित तौर पर अभिनय छोड़ने का फैसला किया है।

सुंदरता के चक्कर में गंवाए कई प्रोजेक्ट्स

करण वाही टेलीविजन के एक मशहूर अभिनेता हैं। वो कई धारावाहिक में नजर आ चुके हैं। हाल ही में करण वाही ने एक खुलासा करते हुए कहा कि ज्यादा सुंदर होने का भी कई बार नुकसान उठाना पड़ जाता है। अभिनेता ने कहा कि सुंदरता के चक्कर में बहुत प्रॉब्लम होती है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक अभिनेता को इस तरह की बात कहनी पड़ी।

अगर मैं किसी शो में हूं, तो वहां वैल्यू भी ऐड करूंगा न

करण वाही हाल ही में कॉमेडियन भारती सिंह के पॉडकास्ट में पहुंचे थे। यहां उन्होंने अपने करियर और आगामी प्रोजेक्ट्स को लेकर बात की। इस दौरान करण ने अपने साथ हुए एक वाकये को भी बताया, जिसमें उन्हें सुंदर होने के चक्कर में नुकसान हो गया। अभिनेता ने कहा, मुझे मुख्य अभिनेता की तुलना में ज्यादा सुंदर होने के कारण कई प्रोजेक्ट्स से हाथ धोना पड़ा है। हालांकि, ये बात मुझे कभी सामने से नहीं बताई गई, बल्कि मुझे दूसरों से इसके बारे में पता चला। मुझे इसके पीछे की सोच कभी समझ में नहीं आती। अगर मैं किसी शो में लीड एक्टर हूं, तो भी मैं उसमें वैल्यू ऐड करूंगा न।

अगर मैं ऋतिक रोशन के साथ काम करता हूं, तो उनका एक स्टारडम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कारण उनके आगे मैं कोई वैल्यू ही ऐड नहीं करूंगा। सुंदरता की वजह से बहुत परेशानी होती है। कई प्रोजेक्ट्स में काम नहीं मिलता। क्योंकि उनका कहना होता है कि आप ये लग नहीं सकते हो, आप ऐसे दिख नहीं सकते हो।

कैसे करण बने बदसूरत लड़के

आगे अपने आगामी कामों को लेकर बात करते हुए करण ने बताया, मेरे पास दो प्रोजेक्ट्स अभी हैं। इनमें से एक बदसूरत दिखने वाले लड़के की कहानी है। इसके निर्देशक मेरे दोस्त हैं, जब वो फिल्म के लिए एक एक्टर ढूंढ रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि किसी और को ढूंढने की बजाय मुझे ही ले लो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पागल है क्या, बदसूरत दिखने वाला लड़का चाहिए है। तू कहां से वैसा लगता है। इसके बाद मैं डेंटिस्ट के पास गया डेंचर्स बनवाए और शेव की। फिर हमने शूट किया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को दिखाया। उन्हें पता ही नहीं चला कि ये मैं हूं।

अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे ने दिल्ली में किया 'केसरी चैप्टर 2' का ट्रेलर लॉन्च

दिल्ली/ भव्य खबर । आखिरकार, बहुप्रतीक्षित फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' का ट्रेलर आउट हो ही गया। 'केसरी चैप्टर 2' का यह ट्रेलर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द इंपीरियल होटल में आयोजित कार्यक्रम में लॉन्च किया गया। अभिनेता अक्षय कुमार और आर माधवन ने अभिनेत्री अनन्या पांडे के साथ अपनी इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अभिनेताओं से सजा फिल्म का नया पोस्टर भी जारी किया गया। यह फिल्म 18 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी। 'केसरी चैप्टर 2' फिल्म वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सी शंकरन नायर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे की सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी थी। ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में 'केसरी चैप्टर 2' के निमार्ताओं करण जौहर, अपूर्व मेहता, अमृतपाल बिंद्रा के साथ फिल्म के निर्देशक करण सिंह त्यागी भी मौजूद थे। फिल्म का नया पोस्टर जारी करते हुए अक्षय कुमार ने भी लिखा, '1650 गोलियां, 10 मिनट और एक आदमी, जो इसके खिलाफ दहाड़ता है। भारत को हिला देने वाले भयानक नरसंहार के पीछे की सच्चाई को देखें।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक अमृता आर पंडित द्वारा साई प्रिंटिंग प्रेस, बी- 868, न्यू अशोक नगर दिल्ली 110096 से मुद्रित तथा ए-115, गली नंबर 13, नई अशोक नगर, दिल्ली 110096 से प्रकाशित।
संपादक - अमृता आर पंडित, मो 8587969284, Mail ID - live18newsnetworktv@gmail.com सभी विवादों के न्याय क्षेत्र दिल्ली न्यायालय में होगा।